

पत्रांक- 398 दिनांक- 10/09/23

सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, अशोक नगर, राँची
की दिनांक-10.09.2023 को 11.30 बजे पूर्वा० में सम्पन्न हुई 62 वीं
ए०जी०एम० की कार्यवाही।

श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य, निदेशक, 303/सी : Good morning everybody. 62 वीं आम सभा के अध्यक्ष डॉ० माधव जी, उपाध्यक्ष के०पी० पाण्डेय जी, सचिव, अनिल शंकर जी, संयुक्त सचिव, शंकर प्रसाद वर्मा जी, निदेशक भट्टाचार्य जी, निदेशक, प्रताप सिंह जी, निदेशक, डॉ० रीता लाल, निदेशक शोभा कुमारी जी, निदेशक श्रीमती कृष्णा श्रीवास्तव जी, निदेशक, इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्य, विशेष कर वरीय सदस्य, आर०के०सिंह साहब, शैल झा, पी०के० वर्मा साहब एवं अन्य सभी सदस्यगण। गर्व की बात है कि इस वर्ष पुनः मुझे आपलोगों के स्वागत का अवसर बोर्ड ने मुझे दिया है, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे गर्व हो रहा है। इस 62 वीं आम सभा में आपलोग का हार्दिक अभिनन्दन है, स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि इस आम सभा में काफी अच्छी चर्चाएँ होंगी, सोसाईटी की जो समस्याएँ हैं उनपर चर्चा होगी और इस साल का जो बजट है वो मेन है उसको हमलोग लेकर आये हैं उसको पास करना है। प्रतिवेदन तो आपलोग को पहले ही दिया जा चुका है। विषय सूची जो है वो ये है कि सबसे पहले स्वागत भाषण होगा। दिनांक-30.04.2023 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन। दिनांक-30.04.2023 की आमसभा की बैठक की सम्पुष्टि। अवैतनिक सचिव द्वारा प्रतिवेदन का प्रेषण किया जाएगा। इसके बाद अध्यक्ष महोदय का संबोधन होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का संशोधित बजट का घटनोत्तर अनुमोदन होगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंकेक्षित आय-व्यय लेखा (तुला पत्र) है। वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित बजट एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के चार माह (दिनांक-01.04.24 से 31.07.24 तक) के प्रस्तावित बजट पर चर्चा एवं अनुमोदन होगा। सोसाईटी के लम्बित भुगतान (देनदारों) की सूची है। माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आवास बोर्ड द्वारा 08 सदस्यों के प्लॉटों के संदर्भ में विचार विमर्श भी करने की जरूरत होगी। न्यायालय में लंबित/निष्पादित मामलों की सूची है उसपर भी चर्चा होगी। ये सब विषय हैं


जिसपर हमलोग चर्चा करेंगे। एकबार पुनः मैं इस 62 वीं आम सभा में आप सबों का अभिनन्दन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने भी वरिष्ठ सदस्य आज यहां उपस्थित हैं सभी लोगों का विशेष रूप से स्वागत है। अब अवैतनिक सचिव महोदय अपना प्रतिवेदन देंगे।

अ0सचिव : नमस्कार, सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लि0, अशोक नगर, राँची की 62वीं आमसभा में आप सभी सदस्यों का स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

विगत कुछ दिनों से पत्नी की इलाज में बाहर रहने के कारण कुछ की गई कार्रवाईयों से अवगत नहीं हूँ। बजट के अभाव में मन्दिर मार्ग में पानी की कमी की समस्या से निदान में विलंब हुई इसके लिए क्षमा चाहूंगा। बोरिंग कहाँ की जायेगी उस स्थान को चिन्हित किया गया है और मन्दिर मार्ग में जल्द से जल्द बोरिंग करायी जायेगी।

वर्ष 2022-23 का ऑडिटेड रिपोर्ट, वित्तीय वर्ष 2023-2024 का प्रस्तावित बजट प्रारूप एवं वर्ष 2024-2025 के प्रथम चार माह का प्रस्तावित बजट का अनुमोदन।

1. जलापूर्ति व्यवस्था:-जलापूर्ति व्यवस्था के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पूर्व से एक लाख गैलन प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही थी। आवश्यकता को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग हटिया योजना प्रमण्डल के साथ एक एकरारनामा किया गया है जिसमें वर्तमान में पेयजल की मात्रा को बढ़ाकर एक लाख पचास हजार गैलन प्रतिदिन करा लिया गया है। साथ ही जहाँ भी जलापूर्ति संबंधी समस्या उत्पन्न होती है वहाँ प्राथमिकता के आधार पर जलापूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जाता है। इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण मंदिर मार्ग में पानी की समस्या खड़ी हो गयी है। इस पर गहराई से नजर रखी जा रही है। समस्या के समाधान हेतु विचार किया जा रहा है। मंदिर मार्ग में पानी की समस्या देखते हुए कोई स्थान चयनित कर बोरिंग हेतु विचार किया जायगा।



2. पथ एवं नाली निर्माण कार्य: वर्तमान निदेशक मण्डल के प्रयास से नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अशोक नगर वार्ड नं0 43 के विभिन्न पथों के किनारे पेभर ब्लाक बिछाने हेतु 2 (दो) करोड़ 44 (चौवालीस) लाख राशि स्वीकृति कराई गई है जिसका कार्य नगर निगम के द्वारा सम्पादित कराई जाएगा। यह आप सबों के सादर सूचनार्थ है।

3. नाली निर्माण : रोड नं0 4/सी 376 से 4 नं0 रोड तक, 396 से 382 तक, सरकारी विद्यालय से 481 तक 94 से 95 तक, पार्क रोड-1, 2 (74 तक) नाली निर्माण कार्य करा लिया गया है, साथ ही अशोक पथ के नाली को पार्क सी में मिलाने साथ ही कुल अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर नाली निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

4. स्ट्रीट लाईट : कॉलोनी के अन्दर सभी स्ट्रीट लाईट का समुचित रख-रखाव किया जा रहा है। जहाँ भी स्ट्रीट लाईट संबंधी कोई भी शिकायत मिलती है, वहाँ तुरंत बदलने अथवा मरम्मत करवाने की व्यवस्था की जाती है।

5. सफाई व्यवस्था : सोसाईटी अपने कर्मचारियों एवं संसाधनों के माध्यम से सफाई कराती रही है। निदेशक मण्डल के प्रयासों से कॉलोनी के अंदर कुल पाँच स्मार्ट डस्टबीन नगर निगम द्वारा लगाये गये है जिससे सफाई व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ है। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर कचड़ा उठाव कार्य भी चल रहा है। साथ ही साथ सोसाईटी भी अपने संसाधनों से नियमित सफाई कार्य कराती है। सफाई व्यवस्था में हुए सुधार आप लोगों को स्पष्ट परिलक्षित हो रहा होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार वृक्षों की छँटाई का भी काम काफी मात्रा में कराया गया है। आगे भी यह काम कराया जायेगा।

6. सुरक्षा व्यवस्था: पुरानी सुरक्षा व्यवस्था के स्थान पर नयी सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया गया है, जिसके परिणाम आप सभी सदस्यों को परिलक्षित हो रहे होंगे। इसके अतिरिक्त गेट संख्या-1,2,4 एवं 6 पर Boom Barrier लगाया गया है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इस कार्रवाई से अनाधिकृत आवागमन, पार्कों के निकट बाहरी लड़के/लड़कियों के जमावड़ा पर

रोक लगाया गया है। बाहरी वाहनों का भी ठहराव समाप्त हुआ है। अभी सुरक्षा की दिशा में और भी सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

7. OPEN GYM : 26 जनवरी 2023, के गणतंत्र दिवस के अवसर पर द्वारा सोसाइटी के अंदर रहने वाले सदस्यों के लिए OPEN GYM पार्क सी में अधिष्ठापित करने की घोषणा की गई थी, जिसे पार्क "C" में अधिष्ठापित किया गया। गार्ड की भी प्रतिनियुक्ति रहती है।

8. माह मई में मजदूर एवं कार्यालय कर्मियों को EPF/ESIC की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

9. विशेष: सोसाइटी के महिला क्लब में बहुप्रतिक्षित रसोई घर का निर्माण के साथ दो अदद ए0सी0 भी लगाया गया है। पुराने थाना भवन जो वर्षों से खाली नहीं हो रहा था उसे खाली कराकर तुड़वाया गया है। इसके चाहरदिवारी का निर्माण कराया गया है।

सदस्यों को पी0एन0जी0 गैस की आपूर्ति हेतु Gail India द्वारा पाईप लाईन घरों तक बिछाने का काम किया जा रहा है, जो प्रायः पूर्ण हो चला है। गैस कनेक्शन के लिए भी Gail India द्वारा Circular निर्गत किया गया है अर्थात गैस Connection देने की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गयी है। यह आप सभी माननीयों के सादर सूचनार्थ है।

अशोक नगर अर्न्तगत जुडको के पाईन लाईन का बिछाने का कार्य समाप्त हो गया है। घरेलु कनेक्शन का ही कार्य बचा है जिसमें सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है।

वृक्षारोपन का कार्य प्रत्येक पार्क में तथा अशोक नगर के सड़कों के किनारे कराई गई है।

वर्तमान निदेशक मण्डल के प्रयासों से विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों में से कुछ मामलों का निष्पादन न्यायालय या आपसी समझौते से कराया गया है। वादों के त्वरित निष्पादन हेतु विभिन्न न्यायालयों एवं अधिवक्ताओं से सतत

सम्पर्क रखा जा रहा है। कृपया प्रस्तावित बजट वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 के प्रथम चार माह के लिए प्रस्तावित बजट को अनुमोदित करना चाहेंगे।

वर्तमान निदेशक मण्डल द्वारा आपके सहयोग से उपलब्ध संसाधनों से ही चहुँमुखी प्रगति की कोशिश की गई है और आगे भी प्रयत्नशील रहेगी। धन्यवाद।

श्री बसंत कुमार भट्टाचार्य, निदेशक, 303/सी : अब अध्यक्ष महोदय प्रारम्भिक संबोधन करेंगे।

डॉ० माधव (अध्यक्ष) : अशोक नगर सोसाईटी के सारे मेम्बर जो आज इस बैठक में उपस्थित हैं उनका मैं अभिनन्दन करता हूँ साथ ही साथ बोर्ड के भी यहाँ जितने निदेशक उपस्थित हैं, ऑफिस वियरर, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परम्परा के हिसाब से मुझे अंत में बोलने की जरूरत होगी लेकिन मैं प्रारम्भ में बहुत शार्ट में बोल रहा हूँ कि यह बैठक बजट पारित कराने के लिए किया गया है। जो पिछले आम सभा में बहुत सारी चर्चाएँ हुई थीं उसको ध्यान में रखते हुए उपाय भी किया गया है। बजट पर चर्चा होने से पहले सदस्यों के जो राय से पहले जो राय सदस्य रखेंगे उसपर विचार किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि सोसाईटी के फायनांशियल Audit महत्वपूर्ण है, परन्तु Performance audit is more Important than any thing जहाँ तक Society का Financial Progress का प्रश्न है, वर्तमान निदेशक मंडल मितव्ययी है Minimum expenditure and maximum performance के साथ काम कर रही है। उसके बारे में मैं दो बातें भी बता दूँ। पहला, परसों से आप लोगों ने जाना होगा ये अखबारों में भी आया है कि 05 तारीख को 02 करोड़, 44 लाख रूपये का टेंडर यहाँ के लिए निष्पादन के क्रम में है, जो पेवर ब्लॉक का है। जो काम पहले हमलोग सरकार से नहीं ले रहे थे किसी भी कारण से, उसके लिए पहल करके नगर विकास विभाग के साथ समन्यवय स्थापित किया है और कई काम हम लोगों ने करना प्रारम्भ किया है। पहला और सबसे बड़ा काम हुआ है पेभर ब्लॉक लगाने वाला, दूसरा काम, अभी हमारी सोसाईटी में नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन 01 से 02 टैक्टर भी दिये जा रहे हैं ताकि घास-फूस, लकड़ी वगैरह काटे जा रहे हैं, सड़को पर रखे जा रहे हैं

उसको नगर निगम के द्वारा ही ढ़ोया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सोसाईटी का जो रेगुलर काम है उसको हमलोग कर रहे हैं, उसमें और सुधार की जरूरत है। परसों से 50 लाईट भी सोसाईटी को नगर निगम ने दिया है और नगर निगम से लगाना भी शुरू कर दिया है जिसमें 20 लाईट शनिवार को लग गये हैं और आज भी लगना था कल से फिर वो लगायेंगे। 50 लाईट फर्स्ट फेज में लगाये जायेंगे उसमें किसी भी प्रकार का पिक एंड चूज नहीं किया गया है।

निदेशक भट्टाचार्य जी, सोसाईटी के इंजीनियर रात्रि में भ्रमण करके जहाँ-जहाँ पर ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं वहां पर प्राथमिकता के आधार पहले लाईट लगाया जा रहा है। उसी तरह आगे भी लगाया जायेगा।

सोसाईटी का ऑडिट हो गया पिछली दफा के बहुत सारे बातें भी हैं कुछ लोगों ने हमें एक स्लीप में दिया है। प्रोसिडिंग में कुछ भी डिलिट नहीं किया जाता है जान बुझकर। कुछ चीजें छूट जाती होंगी लेकिन कोशिश किया जाता है कि हर व्यक्ति की बातों को रखा जाय और इस कमी को दूर करने के लिए हमलोगों ने इस बार प्रोफेशनल प्रतिवेदकों को भी आउटसोर्स किया है इसलिए एक शब्द नहीं छूटेगा। सोसाईटी के सदस्य यह अपने मन से निकाल दें कि बोर्ड जान बुझकर किसी के अंश को डिलिट कर देते हैं या उसको हमलोग नहीं डालें। अब हम केवल ये चाहेंगे कि एजेंडावार चचाएँ हो जाय। बजट पास करने की बात हो जाय, आपलोगों के विचार आ जायें फिर उसपर हमलोग क्या कंप्लायंस कर सकते हैं उसका समाधान क्या उठता है ये बतायेंगे। बोर्ड की तरफ से हमलोग बात करेंगे और इस बैठक में इस प्रतिवेदन में अनुपालन प्रतिवेदन भी दिया गया है, कार्यवाही भी दी गई है, 2022-23 के बजट में जो कुछ चेंजेज हुए थे उसको भी हमलोगों ने सम्पुष्टि के लिए किया है। बजट के टोटल आउटलेट में कोई वृद्धि नहीं हुआ है। जो हमारा रेवेन्यू है या जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसके वियोंड हम नहीं गये हैं, यही कुछ चेंजेज हुए हैं तो किस आधार पर हमने किया है, किस व्यवस्था के तहत हमलोगों ने किया है। इसका 2022-23 का ऑडिटेड रिपोर्ट सबमिट है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कैसे कहाँ से इनकम आयेंगे, कहाँ खर्च होंगे उन सब चीजों का समावेश करके प्रतिवेदन विवरणी दिया गया है। दूसरी बात है कि इस बार जो

बजट हमलोगों ने बनाया है उसमें दो चीजों का ध्यान दिया है। सबों की राय थी मेंटनेंस कॉस्ट में वृद्धि नहीं किया जाय। बिना किसी वृद्धि चाहे वो मेंटनेंस में हो, चाहे वह सिक्यूरिटी में हो, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। पिछली दफा माननीय सदस्य ने फिक्स डिपोजिट के इंटरेस्ट के बारे में भी इंगित किया था उसका भी ध्यान रखा गया है। इस बार हमलोगों ने ट्रांसपेरेंट कर दिया है, प्रतिवेदन में दे दिया है कि सोसाईटी को फिक्स डिपोजिट में कितने पैसे हैं। अभी एक-एक कर माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे और जो सोसाईटी के लिए हितकर होगा, जो बोर्ड के सीमा के अन्दर आयेगा, सोसाईटी के हित के लिए होगा, वो सब काम करने के लिए बोर्ड तत्पर है।

आज की इस 62 वीं आम सभा में सोसाईटी के सदस्यों ने इच्छा व्यक्त किया है कि वे अपने विचार रखेंगे तो मैं शुरूआत कर रहा हूँ डॉ० हासी सरकार से। डॉ० हासी सरकार अपने विचार रखें।

1. डॉ० हासी सरकार, 95/सी : सबों को मेरा नमस्कार। उपस्थित प्रबुद्धजनों एवं ए०एन०एस० के माननीय सदस्यगण और जो ए०एन०एस० परिवार से हैं सबों को मेरा नमस्कार। मैं ए०एन०एस० के बी०ओ०डी० के सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ, निदेशक मण्डल का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ और मैं निदेशक मण्डल को अच्छे और सराहनीय कामों के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ।

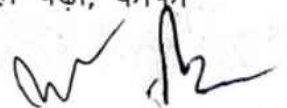
अध्यक्ष महोदय से मेरा एक निवेदन है कि हमारे रोड में लाईट नहीं लगा है। सचिव महोदय ने अभी कहा कि पानी की जो समस्या है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी बोरिंग कराया जा रहा है जगह चिन्हित हो गई है।

दूसरा जो हमारा कहना है वो ये है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रावधान हमारे इस बजट में नहीं है। पहले हमलोग करते थे। हमारा कहना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम सोसाईटी में होने पर बड़ा अच्छा लगता है। अध्यक्ष महोदय से मैं एक निवेदन करती हूँ कि मैगजीन के बारे में। अशोक वाणी पहले मैगजिन निकलता था उसको फिर से निकालने का प्रावधान करें। मेरा कहना है कि म्यूटेशन का काम बहुत जरूरी है उसपर ध्यान दिया जाय। सोसाईटी की साफ-सफाई जैसे

हमारे एरिया में मन्दिर के सामने गंदगी हो जाती है उसके लिए निरंतर प्रयास किया जाय साफ-सफाई रहे और बड़े वृद्धों को छंटवाने की भी आवश्यकता है। हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले चलता था उसको फिर से चलवाने की आवश्यकता है। सालों से हमलोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहा है उसके लिए बजट में प्रावधान करना चाहिए था लेकिन इस बजट में इसका प्रावधान नहीं है इसपर अध्यक्ष महोदय ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है।

सोसाईटी में मच्छरों का भी आतंक है इसपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जो बड़े-बड़े पुराने वृक्ष हैं वो बहुत विशाल आकार ले लिये हैं इसलिए उनको छंटवाने की जरूरत है। आपलोग जो किताब छापीयेगा उस पर मेरा नाम रहे। आपलोग का बहुत-बहुत धन्यवाद और सबको मेरा नमस्कार। आप सब ठीक-ठीक खुशी रहें।

2.श्री आर०के० सिंह, 469/सी : माननीय अध्यक्ष महोदय, निदेशक मण्डल के सदस्यगण, देवियों और सज्जनों। मैंने सचिव महोदय का प्रतिवेदन पढ़ा। 5/सी के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि मॉनिटरिंग नहीं हुआ है। आज हम सुबह मे गये हुए थे तो देखा कि बीच में जो बनाया गया है उसमें पानी भरा हुआ है और काफी गंदगी है उसको ठीक करा लिया जाय। निदेशक मण्डल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमलोग के कॉलनी के लिए इन्होंने 2.5 करोड़ से ज्यादा रूपये सरकार से लिया और उम्मीद है कि हमको उस पैसे से काफी सहूलियत होगी। रोड में जो हमलोग को दिक्कत हो रही थी वह दिक्कत काफी हद तक दूर हो जायेगी। उसके लिए आपलोग को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बधाई। नेक्स्ट बात मैं कहता हूं आय के सम्बन्ध में, किसी भी सदस्य पर किसी तरह का कुछ देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निगम से हमें काफी सहूलियत हो रही है। हमलोग को जो यहां का वेस्ट झिरी भेजना पड़ता था वो बन्द हो गया है जिसके चलते डीजल का काफी सहूलियत हमलोग को हो रही है। उस बचत से हमलोग सोसाईटी में काफी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए निदेशक मण्डल का बहुत-बहुत बधाई। जहां तक श्रोत बढ़ाने की बात है मैं कहना चाहूंगा कि 1990 के आस-पास में हमलोगों ने 25-26 दुकान बनाया था और उसका नॉमिनल रेट रखा था जो अब तक नहीं बढ़ा, काफी



कम है, उसको बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात है कि करीब 01 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा हमारे सदस्यों पर बकाया है। कुछ सदस्यों पर ज्यादा बकाया है उसकी जानकारी हमें नहीं है जिनके पास 50 हजार, 01 लाख रू० से ज्यादा बकाया है, उनपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 403 नम्बर प्लॉट में बहुत ज्यादा बकाया पड़ा हुआ है उसपर ध्यान देने की आश्वकता है। उसमें लोग रहते हैं बिजनेस भी करते हैं लेकिन उनलोग मॅटनेंस चार्ज संभवतः नहीं दे रहे हैं। उसी तरह दो-चार और हैं जिसपर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात है कि जो पानी के लिए कहा जा रहा है या जो गैस केबुल की बात है उसके चलते हम सदस्यों को बहुत दिक्कत होती है। उनको चाहिए कि वो जैसे-जैसे केबुल बिछाते हैं वैसे-वैसे सड़क को भी उसी रूप में बना दें क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाय ताकि हमलोग को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। सुरक्षा के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि गेट पर जो सुरक्षा हो रही है उसपर ध्यान नहीं दिया जाता है। बहुत सारी बाहरी गाड़ियां आती रहती हैं उसपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाय। इसका ध्यान रखा जाए कि जिन गाड़ियों के पास पास हैं वही गाड़ियाँ अन्दर आये। हमलोग का जो ओपेन जीम है उसमें बहुत सारे बाहर के लोग घुस जाते हैं हमलोग के मेम्बर जब जाते हैं तो उनको इन्तजार करना पड़ता है वहां एक रजिस्टर रखा जाय ताकि केवल कॉलनी के लोग ही वहां जायें। बाहर के लोगों को मना किया जाय। हमें बोलने के लिए समय दिया गया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

3. श्री अखिलेश कुमार, 413/बी

: हमारे चेयरमेन साहब, सेक्रेट्री साहब, ज्वाइंट सेक्रेट्री साहब और जो मेम्बर्स यहां पर मौजूद हैं सबो को नमस्कार। लास्ट टाईम जो हमने यहां पर अपने प्वाइंट्स रखे थे, जिसको हमने कहने का प्रयास किया था उसमें बड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। आज के लिए जो है वो हमने प्वाइंट्स बनाकर रखा है। मेरा दो-तीन चीज कहना है।



सर्वप्रथम मैं बोर्ड का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो बहुत जबरजस्त काम कर रहे हैं। बेसिकली वो एप्रीसियेशन के लायक हैं और हमलोग कहें तो हर व्यक्ति का अपना-अपना एक्सपेक्शन होता है और उस एक्सपेक्शन से 100 परसेंट चीजें नहीं हो पाती हैं। हमलोग जब रोड बनाते हैं या केबल लगाते हैं तो उससे इतना पॉल्यूशन होता है और पैसे लगते हैं उसको करने में। जब हमारा घर बनता है तो घर बनाने के बाद हमलोग उसको मेनटेन करते हैं। अक्सर हमारे सोसाईटी के लोगों को पानी का कनेक्शन लेने के लिए या किसी भी कारण से रोड को काटना पड़ता है और रोड बनाने में हमारे इतने पैसे लगते हैं लेकिन जब रोड कटिंग हुआ किसी के फैसिलिटी को कंप्लीट करने के लिए तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारी जो मेंटेनेंस टीम है वो देखे कि जो हमने काम किया था वो यूँ ही पड़ा रह जाता है। उसको रिपेयर करने के लिए किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। अक्सर केबल लगाने के बाद या वाटर कनेक्शन के बाद वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है। उसमें चाहिए कि जैसे ही रोड कटिंग हो काम होने के बाद उसको साथ ही साथ रिपेयर कराया जाय। दूसरी बात है कि जो पेवर ब्लॉक लगाया जा रहा है हम देख रहे हैं कि उसको फेंक दिया गया है। क्या उसकी कोई कीमत नहीं है क्या ? हमारा इंजीनियर, हमारा लेबर जो उस काम को कर सकता है जब काम खत्म हो गया तो पेवर ब्लॉक्स को वापस क्यों नहीं लगा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको भी Importane दिया जाय। मेरा तीसरा ये कहना है कि अभी जो बरसात का सीजन है उसमें सोसाईटी के पेड़ों का ग्रोथ बढ़ जाता है मेरा सजेशन है कि अगर हमलोग बरसात के दिनों में अपने रिसोर्सेस से जो हमारे टैक्टर झिरी नहीं जा रहे हैं उसको यहां इस्तेमाल करें। जस्ट फोर द रेनी सीजन। अभी जो प्रतिवेदन में बताया गया कि वर्ष 2022-23 ऑडिटेड बैलेस सीट हमारे पास में आया है। यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमलोग का जो फिक्स एसेट है 23 लाख, 81 हजार का उसको रेड्यूस् किया हुआ है और जो प्रेजेंट स्टेटमेंट है उसमें मिल रहा है 18 लाख, 08 हजार रूपया। यानी मोटा-मोटी 02 लाख 96 हजार। तो ये जो है वो घटा है दैट मिंग हो सकता है कि ये निगोशियेशन में जाये लेकिन इसको अगर रिमूव किया गया है, इसको डिस्पोजल किया गया है उसमें 03 लाख का रेवेन्यू एमाउन्ट हमलोग का आया ह, रिसीभ हुआ है हमारे एकाउन्ट में। तो ये जो 03

लाख रूपया का हमारा अमाउन्ट है उसको इसमें दिखना चाहिए था। दूसरा हमारा कहना है कि प्रतिवेदन में केसेस का प्रजेंट स्टेटस दिया हुआ है। इसमें एक चीज ये है कि एक क्रिमीनल केस फाईल किया था हमने मेरा ये कहना है कि ये जो 31 लाख रूपये चार-पांच साल से हमलोग दिखाते आ रहे हैं कि इतना पैसा हमने दिया हुआ है उस केस का क्या स्टेटस है? What is the status of that particular case. उसके बारे में यहां पर कोई मेशन नहीं है कि उस केस में क्या प्रोग्रेस है। बाकी सब अच्छा है। धन्यवाद।

4. श्री के०के० शर्मा, 98 सी : आज की आम सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, सचिव जी, संयुक्त सचिव जी, निदेशक मण्डल और हमारे सोसाईटी के सदस्यगण का मैं अभिनन्दन करता हूं। मैं 98/सी मन्दिर मार्ग, मन्दिर के सामने रहता हूं मेरा नाम के०के० शर्मा हुआ। मुझे सबसे पहले बात करनी है वहां के वाटर सप्लाई के बारे में, पानी के बारे में। मंदिर से लेकर रोड नम्बर-1 तक पानी की इतनी दिक्कत हो गई है जिसका कोई जवाब नहीं है। 10 अप्रैल से हमारा पानी बन्द है कुछ लोगों को मिलता था पानी लेकिन एक-डेढ़ महीने के बाद उनलोग का भी पानी बन्द हो गया। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारा बोरिंग फेल कर गया था उसके बाद फिर से मैंने बोरिंग करवाया तो हमको पानी मिल रहा है। हमारे बगल में सुजाता सहाय है जो 97/सी में रहती हैं उनकी तो दुर्गती हो गयी। मैं उनको अपना पानी देता रहा 10-15 दिन ये स्थिति हो गई है लेकिन किसी के कान पर जूँ नहीं रेंगा। मैं सेक्रेट्री को बार-बार लिखा, सेक्रेट्री क व्हाटसअप पर लिखा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अन्त में अध्यक्ष महोदय की कृपा से एक मिटिंग हुई जिसमें सचिव महोदय नहीं थे हमारे एरिया से सभी लोगों को बुलाया गया था उसमें चेयरमेन साहब ने कहा कि बोरिंग होगा। लेकिन फिर पता नहीं क्या बात हुई बीच में कुछ अडचन पड़ रहा था अभी तक बोरिंग नहीं हुआ। तो मेरा अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वहां जल्द से जल्द बोरिंग करवायें। आप नाली बनवा रहे हैं सब काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन सबसे जरूरी पानी है उसको आप जल्दी कीजिए। उसमें मेरा एक सुझाव है कि आप जो बोरिंग करवा रहे हैं वो बोरिंग ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि वाटर लेबल डाउन हो रहा है। आपको पानी

की समस्या से निजात दिलाने के लिए यथाशीघ्र एक वाटर टावर बनवाने की आवश्यकता है ताकि पानी बराबर मिल सके। अगर इसके लिए पी0एच0ई0डी0 की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए पहल करके उसको बनवायें। इसके अलावा बोरिंग से भी पानी दें। हम चाहेंगे कि बजट में जो मेंटनेंस कॉस्ट 10 लाख रुपया रखा गया उसको बढ़ाकर 01 करोड किया जाय। हमने यह भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने घर के सामने जो जगह है उसको घेरकर बगीचा बना लिया है ये सब कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि आप छूट दिये हुए हैं। एक भी नोटिश इसके लिए आपने किसी को नहीं दिया है। ऐसे लोगों का आप नोटिश दीजिए और अगर आप नोटिश नहीं देते हैं तो हम समझेंगे कि इसमें आपकी सहमती है। हमलोग के एरिया में साफ-सफाई की आवश्यकता है उसपर ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा मेरा कहना है कि पार्क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है पार्क की स्थिति बहुत खराब हो गई है उसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्क में झाड़ियां उग आई हैं, बड़े-बड़े घांस हो गये हैं, पार्क की साफ-सफाई और मेंटनेंस की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि सोसाईटी के रोड घर के बार कचड़ा फेंक देते हैं उसको डोर-टू-डोर उठवाने की जरूरत है ताकि साफ-सफाई रह सके। हमने अपने घर के सामने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा टैंक बनवाया था हमारे जितने लोग हैं वो कचड़ा उसी में रख देते थे इसके लिए सबको ध्यान देना होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना विचार समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

5. श्री पी0 के0वर्मा 155/सी : हमारे कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी के सभी सम्मानित सदस्यगण, आपलोगों का बहुत-बहुत जोहार और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद कि उन्होंने बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं हमारे ऑनररी सेक्रेट्री ने जो उद्बोधन दिया है उसके एक बिन्दु पर मैं ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा, इस आशय का, अब एग्जैट भरबेटिंग तो हम नहीं लिख पाये। उन्होंने कहा कि विगत कुछ समय से वे अपनी पत्नी की ईलाज में व्यस्त रहने के कारण कुछ चीजों से अवगत नहीं हैं। ठीक है, उनका पर्सनल चीज है। मैं इस सम्बन्ध में उनसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बी0ओ0डी0 ने जो ये प्रतिवेदन सरकुलेट किया है इस बैठक के लिए उससे वे पूर्णतया सहमत है या नहीं? इसको

ओन करते हैं या नहीं? यदि नहीं, तो ये बतायें कि किन-किन चीजों से ओन नहीं करते हैं। उनके पर्सनल मैटर से बीओडी का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि वे किन्हीं बातों से सहमत नहीं हैं तो उन्हें उस एजीएम को बताना चाहिए कि किन बातों से वो सहमत नहीं हैं। अन्यथा एजीएम ये मानेगा कि वे इस प्रतिवेदन और उसमें लिखी सभी बातों से पूर्णतया सहमत हैं। ऑनररी सेक्रेट्री साहब प्लीज रिस्पॉड कीजिए। क्या आप इससे पूर्णतया सहमत हैं या नहीं हैं?

अ० सचिव : कुछ बिन्दु पर हम नहीं थे उस समय मीटिंग हुई है उससे हम सहमत नहीं हैं।

श्री पीके वर्मा : सेक्रेट्री साहब, यू प्लीज कम टू द डायस और इस एजीएम को बतायें कि आप इस प्रतिवेदन में लिखी किन-किन बातों से सहमत नहीं हैं। इट मस्ट बी एक्सप्लेटिव एंड इट मस्ट बी ऑन रिकार्ड। मैं तब तक स्टेज खाली कर रहा हूँ।

(इस अवसर पर अ० सचिव स्टेज पर नहीं आये)

श्री पीके वर्मा 1: Service of Meeting मैं सबसे पहले जो नोटिश का पत्र निर्गत है दिनांक-23.08.2023 की तिथि में और यह मुझे दस्ती माध्यम से दिनांक-31.08.2023 को मिला। मैं इसी कॉलोनी में रहता हूँ और इस पूरी अवधि में यहीं था। अतः अ० सचिव महोदय जाँच करना चाहेंगे कि इस पत्र की Service में 08 दिन कैसे लग गये।

हमारे सोसाईटी के Bye-Laws का नियम इस कार्य-प्रयोजनार्थ "14 Clear days का न्यूनतम समय प्रावधानित करता है।

2. दिनांक-30.04.2023 को AGM की संपन्न 61वीं बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि का औपचारिक प्रस्ताव नहीं लाना : आहूत 62 वीं बैठक की विषय-सूची में 61वीं बैठक की कार्यवाही तो दी गयी है, परंतु इसकी औपचारिक संपुष्टि का प्रस्ताव अंकित नहीं है। विषय-सूची के क्रमांक-3 में अंकित विषय से केवल यही संपुष्टि होगा कि दिनांक-30.04.2023 को बैठक हुई थी, परंतु इससे बैठक की कार्यवाही की automatic संपुष्टि नहीं हो जाएगी। अतः बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि हेतु औपचारिक प्रस्ताव वांछित हैं। आपको अपना संशोधन डिक्लियर करना चाहिए।

3. 61 वीं बैठक की कार्यवाही: इस बैठक के Minutes of Proceeding में दर्ज अनेक बातें problematic (समस्या-मूलक) हैं। इन्हें Expunge करने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें अनेक बातों का समावेश नहीं किया गया है। किसी बैठक का Minutes of Proceeding जारी करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि यह किसी Court of Law में Admissible होता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा।

(क) जो लिखना छूट गया है : प्रतिवेदन-पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 9-10 पर मेरे द्वारा व्यक्त कुछ विचारों एवं सुझावों को अंकित किया गया है। परंतु इसमें अनेक महत्वपूर्ण बातों, जिन्हें मैंने कहा था, का समावेश नहीं है। जैसे- Fixed of Deposit Interest source से वर्ष 2022-23 में प्राप्त आय का आँकड़ा बहुत कम (6.56 लाख रू0) दिया गया था। मैंने इसकी तुलना पूर्व के तीन वित्तीय वर्षों से करके यह सुझाव दिया था कि इसे पुनः चेक किया जाये क्योंकि ऐसा तभी संभव हो सकता था जब कुछ F. Ds को तोड़ा गया हो।

इस संबंध में Proceeding में मात्र इतना दर्ज है- Interest on F.D. में जो 21-22 में" क्या मतलब है इसका?

(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 में Exp.on Honorarium के बारे में कहा था कि इसके लिये कोई बजट स्वीकृत नहीं था परंतु फिर भी व्यय किया गया। साथ ही Bye-Laws के संगत प्रावधानों के आलोक में इसकी non- admissibility एवं इसके प्रभावों की चर्चा करते हुए यह सुझाव दिया था कि इस पर Legal opinion प्राप्त कर आवश्यक अग्रत्तर कार्रवाई की जाय।

(iii) Paper Block in Road कार्य पर हुए अधिकार्ई व्यय को इंगित करते हुए इसके विधिवत regularization का सुझाव दिया था।

(iv) सोसाईटी के Bye-Laws के नियम- 30 (i) का हवाला देते हुए re-appropriation mechanism की बात भी मैंने कही थी।

(v) Rent from Shops में वृद्धि के प्रस्ताव के संबंध में इसके संभावित Legal implications को रेखांकित करते हुए यह सुझाव दिया था कि BOD द्वारा संबंधित दुकानदारों से बातचीत कर आपसी सहमति के आधार पर अग्रत्तर कार्रवाई करना यथोचित होगा।

(vi) वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट में Maintenance & Security Charges के Sub-Heads (Receipt section) के प्रस्तावित merger के होनेवाली संभावित

कठिनाईयों को इंगित करते हुए इन्हें पूर्व की भाँति अलग-अलग ही रखने का सुझाव दिया था।

(vii) Salary of Regular Staff, Daily Wages Labour तथा contingency Sub- Heads (Expenditure section) में वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित राशि के अधिक होने की विवेचना भी किया था।

(viii) Renovation, Upgradation and widening of Road etc. Sub-Head (Exp. section) के लिए Site Plan, Estimates आदि की आवश्यकता बताते हुए "Any Development Work" जैसे vague शीर्षक को हटाने का सुझाव दिया था।

(ix) Society के Bye-laws के नियम-51 (i) का हवाला देते हुए Reserve fund के सृजन की बात कही थी।

(x) P.P mode पर कार्य कराने हेतु लिये गये प्रस्ताव पर भी मैंने अपनी विवेचना एवं सुझाव दिया था।

ये सभी बातें मैं अपनी Memory के आधार पर कह रहा हूँ। संभव है इनके अतिरिक्त भी कुछ बातें हों, जो Minutes of Proceeding में दर्ज करने योग्य हो। उस दिन (30.04.23) की बैठक में कार्यवाही की Video recording भी हुई थी। इसे देखना यथोचित होगा।

(ख) जो नहीं लिखा जाना चाहिये था: अध्यक्ष महोदय के अभिभाषण के कुछ अंश उदाहरणस्वरूप समीचीन है:-

(2) पृष्ठ संख्या-23 पर दर्ज यह बात - "हमलोगों ने सोचा कि मेम्बर्स को बताऊँ और इसके पहले भी हर तीन महीने का व्यय जो Grievance Cell और इसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सदस्यों को अवगत कराते रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ी या अनियमितता हो रही है, तो सूचित करेंगे और उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे।"

(a) इस statement में परिणाम गंभीर एवं खतरनाक हैं तथा इस समिति के सभी सदस्यों की सुरक्षा से संबंधित हैं।

(b) हर तीन महीने का व्यय "अर्थात् Quarterly Expenditure Statement जो कि एक विहित प्रपत्र में तैयार होता है।

(c) प्रश्न है कि ऐसा कोई Statement कब-कब और किस format में Grievance cell एवं अन्य किस सोशल मीडिया पर किसके द्वारा upload किया गया है?

(d) "Grievance Cell Ashok Nagar" नाम से एक WhatsApp Group सोसाईटी कार्यालय द्वारा संचालित है जिसके Group admin हमारे समिति के Hony Secy हैं तथा जिसके लगभग 280 सदस्यों में से मैं भी एक सदस्य हूँ।

मुझे स्मरण नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कोई Quarterly Expenditure statement देखा है।

(e) इसके अतिरिक्त अन्य किस सोशल मीडिया की बात कही गयी है।

(7) इस सोसाईटी में प्लॉट्स की संख्या 500 से अधिक है। अतः इसके सदस्यों की संख्या की 500 से अधिक होगी। तथाकथित Quarterly statement किनको मिला है?

(8) क्या तथाकथित त्रैमासिक स्टेटमेंट देते समय जिसमें यह भी अनुरोध किया गया था कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता देखे जाने पर सूचित करेंगे?

(b) क्या इस प्रकार के कार्य सोशल मीडिया पर होते हैं?

(c) राशि आहरण एवं व्यय कार्य में सोसाईटी कार्यालय के Drawing & Disbursing Officer (DDO) की जिम्मेदारी क्या है?

इस प्रसंग में सभी को याद रखने की आवश्यकता है कि दिनांक-30.04.2023 को 61 वीं बैठक में BOD द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्तावों सहित अन्य प्रस्तावों पर भी सदस्यों ने आपत्तियाँ की थी।

(ii) पृष्ठ संख्या-23 पर दर्ज यह बात:-"ये एक established/professional office नहीं है।

यह सोसाईटी 60 वर्षों से भी अधिक पुरानी है तथा इसके Bay Laws बने हुए हैं इसके प्रबन्धन के लिये समय-समय पर BOD का चुनाव होते रहा हैं। बैठकें होती रही हैं और कार्यवाही प्रतिवेदन जारी होते रहे हैं। Audit भी होते रहा है। BOD की सहायता के लिए तकनीकी स्टाफ नियुक्त है। बाहर से सहायता या परामर्श प्राप्त करने के लिये सुविधा/संसाधन उपलब्ध हैं आदि।

मेरा तो मानना है कि हमारी सोसाईटी राज्य के उन गिने-चुने established professional societies में से एक है जिसे एक वेबपमजल के रूप में उदाहरण दिया जा सकता है।

फिर भी यदि BOD को लगता है कि समिति कार्यालय के और सुदृढीकरण की आवश्यकता है, तो उसे सम्यक प्रस्ताव सृजित कर AGM के समक्ष लाना चाहिये।

(iii) पृष्ठ संख्या-44 पर दर्ज यह बात- "वर्मा साहब को यह भी खयाल होगा कि जब Revenue Receipt & Expenditure statement state Govt. का बनता है, जो गैप होता है-उसको कहते हैं Founding from other sources, i.e. Financial Institution "

वर्मा साहब को इस बात का खयाल है, परंतु बैठक की कार्यवाही में यह बात लिखने का occasion कहाँ है?

यह रिकॉर्ड पर है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट एक Deficit Budget नहीं था। इसी प्रकार 61 वीं बैठक एवं अब 62वीं बैठक के लिये BOD द्वारा प्रस्तुत बजट भी Deficit Budget नहीं है। अतः तथाकथित Gap कहाँ है? ऐसी स्थिति में इन Budget की पूरी या आंशिक Founding from other sources, i.e. Financial Institutions etc. का प्रश्न कहाँ उठता है? यह प्रश्न तो तब उठता है जब बजट में सकल प्राप्ति की तुलना में अधिक व्यय का प्रस्ताव सूचित किया जाता है।

(iv) पृष्ठ संख्या-26 पर दर्ज यह बात-"बैठक हेतु Agenda का निर्धारण Chairman और Board तय करेगा। ये Members तय नहीं करेंगे।"

किस मेम्बर ने के इस Chairman/Board के इस अधिकार को चुनौती दिया है? यह अधिकार तो BOD में ही निहित है।

मेम्बर्स तो सिर्फ अपनी बातें कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं या किसी बात को Agenda में शामिल करने का अनुरोध कर सकते हैं। इस पर ससमय BOD द्वारा यथोचित निर्णय लेना एवं संबंधित पक्ष को अवगत करना वांछित है।

समिति के मेम्बर्स का ऐसा कोई कार्य आपत्तिजनक या BOD के लिये चुनौती कैसे हो गया?

(v) पृष्ठ संख्या-26 पर दर्ज यह बात-"जैसे एक Amendment क्लॉज 28 में है कि अगर 21 आदमी आयेंगे तो कोरम पूरा हो जायेगा। को-ऑपरेटिव एक्ट कहता है कि 20 प्रतिशत 7 the strenth पर amendment बाहयत्ता है Bye-laws में।

यद्यपि कथन में claring नहीं है तथापि यह मान हो रहा है कि बात किसी आम सभा की बैठक के संदर्भ में कोरम की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कही गयी है।

मैंने प्रयास किया कि ये बातें किस एक्ट या रूल या Bye-laws में प्रावधानित है। अभी तक खोज की स्थिति यह है कि हमारे सोसाइटी के Bye-laws या The Jharkhand Co-operative Soc Rules, ACT, 2008 की धारा/नियम 28 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

समिति के जेनरल बॉडी के जेनरल मीटिंग के लिये सोसाइटी के Bye-laws के नियम-38 में प्रावधान यह है कि—"The quorum of the general meeting shall be thirty or one fourth of the total number of members whichever is less"

The Jharkhand Co-operative Soc Rules, ACT, 2008 की धारा/नियम -21(4) में इस प्रयोजनार्थ निम्नवत प्रावधान है।

Unless otherwise provided in there rules or in the Bye-laws the quorum for a general meeting shall be one fifth of the total membership ot the society on the date of issue of the notice of the meeting."

अतः स्पष्ट है कि जब हमारे सोसाइटी के ठलम सूँ में इस कोरम के प्रयोजनार्थ नियम बना हुआ है, जैसा कि यहां अंकित किया गया है, तो वही लागू होगा। यदि आम सभा की जेनरल मीटिंग में तीस सदस्य उपस्थित हैं, तो कोरम की पूर्ति होती है। यदि कोई confusion है, तो Bye Laws के नियम-56 के अंतर्गत इसे Register, Co-iopertaive Society, Jharkahn के पास निर्णय हेतु refer करने का अनुरोध है और यदि पूर्व में इसे refer करके कोई नियम प्राप्त किया गया है, जो उससे अवगत कराया जाये।

(vi) पृष्ठ संख्या-29 पर दर्ज यह बात "कोई भी बात बता दीजिये कि आपके पास कोई फॉर्मूला है कि मेन्टेन्स का क्या होना-चाहिये, सिक्यूरिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिये, तो आपको Most welcome है। परंतु किसी कोने से यह सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।"

आश्चर्य है पूरी कार्यवाही इन दोनों विषयों पर सदस्यों के सुझावों से भरी पड़ी है कई फॉर्मूला भी सुझाये गये हैं। परंतु फिर भी यह बात कार्यवाही में लिखी गयी।

(vii) बैठक की कार्यवाही में और भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें दर्ज हैं। कहीं तक कहा गये, परंतु एक वरिष्ठ सदस्य द्वारा उस दिन बैठक में कही गयी एक बात

को मैं यहाँ जरूर quote करना चाहूँगा जो कि कार्यवाही में भी दर्ज कर दी गयी है—“आम सभा में बजट पर सभी microscope से देखता है।”

हालांकि उस दिन माननीय सदस्य ने यह बात भयावेश में कह दिया था परंतु देखिये कि BOD के प्रस्तावों को microscope से देखने का क्या सुखद परिणाम निकला है, जैसे—

(a) F.D. पर interest प्राप्त 5.56 लाख रू० से बढ़कर अब 43.72 लाख रू० हो गयी है।

(b) इसी प्रकार society charges में एवं Misc.Receipt में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

(c) इसी प्रकार पहले जो 290.02 लाख रुपये की सकल प्राप्ति दिखायी गयी थी, वह अब बढ़कर 343.04 लाख रू० हो गयी है, अर्थात् 53.02 लाख रुपये की वास्तविक वृद्धि हो गयी और त्रुटि—सुधार भी हो गया।

(d) यह भी संपुष्ट हो गया कि कोई F.D. नहीं टूटा है।

(e) वर्ष 2023-24 के लिये salaries of Regular Staff में प्रस्तावित व्यय—आकलन अब घटकर 30.00 लाख रू० हो गया। यहाँ भी 10.00 लाख रू० की बचत हुई।

(f) मेरी सोच है कि उस दिन यदि शांति के साथ मेंटेन्स चार्ज एवं सोसाईटी चार्ज पर थोड़ा मंथन किया गया होता और बैठक abruptly नहीं समाप्त कर दी गयी होती, जो कुन-न-कुछ रास्ता अवश्य निकलता और इनमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये अतिरिक्त रूप से लगभग 30.00 लाख अतिरिक्त प्राप्ति की संभावना बन जाती।

यह आकलन ठक्क द्वारा 61वीं बैठक हेतु दिये गये प्रतिवेदन के पृष्ठ सं० II एवं III पर दी गयी सूचनाओं पर आधारित है जिसमें अंकित है कि आवासीय उपयोग वाले plots से लगभग 15.00 लाख रू० एवं सुरक्षा शुल्क में लगभग 6.00 लाख रू० प्रति वर्ष प्राप्त होती है।

(g) लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उक्त सदस्य भी यह बात proceeding में नहीं लिखी जानी चाहिए थी क्योंकि य न केवल उनके लिये embarrassing है, बल्कि सभी सदस्यों के अपमानजनक भी है।

अतः 62वीं बैठक हेतु दिये गये प्रतिवेदन में प्रस्तुत 61वीं बैठक की कार्यवाही को recast करके प्रस्तुत किया जाना है। कुछ हटाना है और कुछ जोड़ना है। इसे वर्तमान स्वरूप में स्वीकार या संपुष्ट नहीं किया जा सकता।

(4.) वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट का घटनोत्तर अनुमोदन यह संभव नहीं है क्योंकि-

(i) Higher authority द्वारा स्वीकृत बजट को lower authority द्वारा संशोधित (revise) नहीं किया जा सकता। lower authority द्वारा इस संबंध में मात्र प्रस्ताव Higher authority को दिया जा सकता है। यहां Higher authority से तात्पर्य समिति की आमसभा (AGM) तथा lower authority से तात्पर्य समिति के BOD से हैं।

(ii) BOD द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव घटनोत्तर स्वीकृति (post-factoapproval) का है, अर्थात् BOD द्वारा पहले ही अपने स्तर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के ए0जी0एम0 द्वारा स्वीकृत बजट का revision किया जा चुका है।

अतः BOD यह स्पष्ट चाहेगा कि उसे ऐसा करने की शक्ति किस स्तर से प्राप्त (delegated) है।

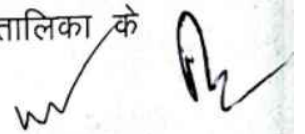
(iii) जैसा कि पूर्व में ही यह कहा जा चुका है, वित्तीय वर्ष 2022-23 समाप्त हो चुका है। अतः अब तो यही प्रश्न समीचीन है कि ए.जी.एम द्वारा स्वीकृत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति एवं व्यय की क्या वास्तविक स्थिति रही है।

(iv) इसी प्रसंग में यह गौरतलब है कि व्यय से संबंधित मात्र दो Items Irregular expenditure की श्रेणी में आते हैं। 1. Exp. on Honorarium, जिसके लिये बजट में प्रावधान नहीं है था परंतु व्यय हुआ और यह गलत सूचना भी दी गयी कि इसके लिए 3.00 लाख रू0 का बजट स्वीकृत था तथा 2. Paver Block in Roads, जिस पर बजट प्रावधान से लगभग 120 प्रतिशत अधिक राशि व्यय की गयी।

(v) इन दोनों irregular expenditures के लिए 61वीं बैठक में सुझाव दिया गया था कि Legal/financial, audit experts से परामर्श कर संगत तथ्यों के साथ इनके regularization हेतु प्रस्ताव सृजित किये जाये और आवश्यक कार्रवाई हेतु इन्हें AGM की बैठक में लाया जाये।

परन्तु ऐसा न करके indirect तरीके से संपूर्ण बजट को ही संशोधित करके इसकी घटनोत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव लाने का क्या औचित्य है?

(vi) इस प्रसंग में Revised Exp, Budget की जो तालिका दी गयी है (पृष्ठ सं0-37), उसमें अंकित कुल 27 Budget Sub-Heads में से 25 Sub-Heads में AGM द्वारा स्वीकृत राशि से कम राशि व्यय हुई है। साथ ही तालिका के



कॉलम सं०-4 में इनके विरुद्ध जो संशोधित राशियाँ लिखी हुई हैं, वे वास्तविक व्यय से अधिक हैं। क्या प्रयोजन है?

कमोवेश यही स्थिति Revised Revenue Receipt से सम्बन्धित तालिका (पृष्ठ सं०-36) की भी है।

(vii) और अब तो वित्तीय वर्ष 2022-23 का अंकेक्षण (audit) भी हो चुका। परन्तु पूरा audit report प्रतिवेदन में नहीं दिया गया है, जिससे यह पता नहीं चलता कि इस अंकेक्षण कार्य में AGM द्वारा स्वीकृत बजट के आँकड़े लिये गये हैं या BOD द्वारा revised आँकड़े।

(viii) अतः इस प्रसंग में मेरा सुझाव है कि -

(a) Receipt & Expenditure से संबंधित प्रतिवेदन उसी format में दिया जाये जिसमें Budget सक्षम स्तर (AGM) द्वारा स्वीकृत था।

(b) Paver Block in Road कार्य एवं Exp. on Honorarium के irregular व्यय के नियमितकरण हेतु संगत तथ्यों/सूचनाओं के साथ प्रस्ताव सृजित कर अलग से AGM की बैठक में लाया जाये। कार्रवाई हेतु बैठक में लाया जाये।

(5) वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रस्तावित बजट

(i) बजट प्रस्ताव अभी भी उस Format में सृजित नहीं है जिसमें पहले से होता आया है। अतः यह पता नहीं चलता कि Receipt section में Revenue Receipt एवं capital receipt का क्या आकलन या पूर्वानुमान है तथा Expenditure section में Revenue Expenditure, capital Expenditure एवं Deposit Work Expenditure का क्या प्रस्ताव है।

निर्धारित प्रपत्र में बजट-प्रस्ताव का सृजन नहीं करना सोसाईटी के लिए भविष्य में समस्याएँ खड़ी करेगा- यह 61 वीं बैठक में ही इंगित करेगा।

अतः पुराने Format में ही बजट का सूत्रण करने का पुनः सुझाव है।

(ii) Daily wages Labour शीर्ष में अभी भी 70.00 लाख रूपये का प्रस्ताव बिना किसी detail के दिया गया है। यही माँग (70.00 लाख की) 61वीं बैठक में भी की गयी जिसपर अनेक सदस्यों ने reservations प्रकट किया था।

इसमें कुछ कटौती आवश्यक है।

(iii) Contingent Expenses में 50.00 लाख रू० की माँग है जो बहुत ज्यादा है। इसके लिये तालिका के Footnotes में अंकित कुछ items जैसे -

Health & Hygiene, office exp (including printing & stationary), Holding Tax Expense, Hoarding & Advertisement हेतु अलग-अलग राशि की माँग वांछित है।

Pantry Expenses एक Vague शीर्ष/नाम है जिसका विस्तार अनन्त है। Labour payment हेतु माँग Repetition है। इसके लिये तो Daily Wages Labour शीर्ष में अलग से राशि की माँग है ही।

इस प्रकार Contingent Expenses शीर्ष में केवल Unforeseen/Misc Exp (including local conveyance) हेतु कुछ राशि की माँग किया जाना वांछित होगा।

(iv) Water supply मद में प्रस्तावित राशि अधिक राशि की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस वर्ष rains की कुछ बेरुखी तथा सदस्यों की कठिनाई विद्यमान रही है। भविष्य में भी इसकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। कुछ अतिरिक्त बोरिंग आदि कार्य कराने पड़ सकते हैं। अतः पहले से ही तैयार रहने में कोई हर्ज नहीं है।

(v) Exp. on Honorarium तथा Renovation, up gradation and widening of Road etc. के प्रस्ताव के साथ संगत सूचनायें नहीं दी गयी हैं।

(6) वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चार महीनों का प्रस्तावित बजट प्रस्तुत तालिका के क्रम संख्या-5, 6, 10 एवं 13 पर मेरा मंतव्य वही है जो इन कार्यों के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये प्रस्तावित बजट के सम्बन्ध में दिया गया है।

(7) वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंकेक्षित लेखा (audited accounts) को AGM द्वारा adopt करने हेतु BOD द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं लाया गया है। ऐसा किया जाना सोसाईटी के Bye-laws के नियम 40 (b) के तहत वांछित है। पूरा Audit Report दिया जाना आवश्यक है, मात्र इसके एक हिस्से (P/L Account तथा Balance sheet) का दिया जाना पर्याप्त नहीं है।

(8) सभी प्रकार के Outstanding Dues की वसूली हेतु विशेष प्रयास किया जाना वांछित है।

इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।

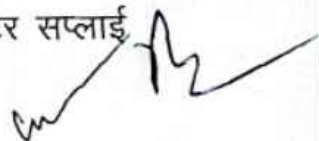
6. श्रीमती शैल झा, 229/सी : ये बिल्कुल ठीक है पीक एंड चूज न किया जाय। मैं तो हमेशा हाजिर हूँ। मुझे दो शब्द बहुत अच्छे कहने हैं। जैसे रेगिस्तान में दो बुंद पानी पड़ने के सबों को आस रहती है मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत ही

ज्यादा गरम हवा चल गई तो मैं थोड़ी शांति और शितलता का लेप करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे निदेशक मंडल को और धन्यवाद इसलिए कि आपने अशोक नगर सम्पूर्ण महिला समाज के लिए बहुत ही नेक कार्य किया है। हमारे हॉल में अब दो-दो ए0सी0 लग गये हैं। हमारे रसोई घर की व्यवस्था हो गई है जो आशा के विपरित है। हमलोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी अधिक सुविधायें हमें इतनी जल्दी मिल जायेंगी। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और आप सभी लोगों का मैं अभिनन्दन करती हूँ और अगर सभी शांतिपूर्वक किसी भी समस्या का समाधान ढूँढे तो निदान मिल जाएगा और अगर गर्म हवा ज्यादा चली तो ए0सी0 की ठंडक भी कुछ नहीं कर पायेगी। धन्यवाद।

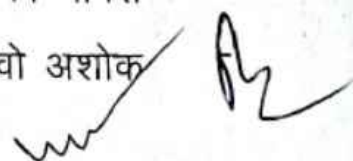
7. श्री महेश्वरी प्रसाद, 162/सी : 62 वीं आम सभा की बैठक में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, संयुक्त सचिव महोदय, निदेशक मंडल के सदस्य और अशोक नगर सोसाईटी के सदस्यगण, मैं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट पर बोलना चाहंगा कि अभी तक एक्युअल एक्सपेंडिचर 02 करोड़, 40 लाख है लेकिन आप 04 करोड़, 50 लाख के लिए ये पोस्ट पैक जो सैंक्शन देते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि ग्रीभांस सेल में हरदम तीन-तीन महीना पर भेजते थे एक्सपेंडिचर वो हमलोग को नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए हम इससे पूर्णतः सहमत हैं और डिटेलिंग भी नहीं है कि क्या एक्सपेंडिचर आप कीजिएगा। सचिव महोदय के भाषण में लिखा हुआ है ये बहुत भेग है। इसमें लिखा है विशेष पथों में, कौन-कौन पथ है? पथ और नाली निर्माण का, अन्य बहुत महत्वपूर्ण, ये सब तो एकजैट देना चाहिए था न। मैं इसमें अमेंडमेंट के साथ सहमत हुआ। दूसरा ड्यूज के बारे में लगता है आपलोग कोई कार्रवाई नहीं किये वो 92 लाख से 01 करोड़ पहुंच गया। इसके क्या है। आपलोग कोई पत्राचार किये या सर्टिफिकेट केस किये? कोई सर्टिफिकेट केस नहीं किये। ड्यूज बढ़ा है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट केस भी नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि जो 50 हजार से उपर है उसपर सर्टिफिकेट केस और जो कम्लीकेटेड ड्यूज है जैसे 403 हुआ और भी जो है उसके लिए अच्छा लॉयर रहें, एक कमिटी बना दीजिए उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि 403 का हमको

याद है कि हमलोग रिभ्यू कराये थे कोर्ट में जो कि लम्बित था लेकिन उसका लिगल वाला स्टेटस में कोई जिक्र नहीं है। धन्यवाद।

8. श्री राम कुमार तिवारी, 182/सी : मैं राम कुमार तिवारी 182/सी का निवासी हूँ ये मेरा परिचय है। मैं निदेशक मण्डल का अभिनन्दन करता हूँ। कुछ बिन्दुओं पर मेरा निदेशक मण्डल, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं संयुक्त सचिव महोदय का ध्यानाकर्षित करना है और मुझे ऐसी उम्मीद है बी०ओ०डी० इसपर पहल करेगा। पहला, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं बी०ओ०डी०, निदेशक मण्डल तथा आये हुए सभी को-ऑपरेटिव के मेम्बर्स का मैं स्वागत करता हूँ। पहली बात है कि मैं 04 नम्बर रोड में रहता हूँ और वहां से 30 के०वी०ए० का लाईन जो सबसे ऊंचा ट्रांसमिशन लाईन है वो अन्डरग्राउण्ड केबलिंग करके ले जाया गया है जिस पर हम और सेक्रेट्री साहब स्कूटी पर सवाल होकर हमलोगों ने देखा था कि 16 केबुल अन्डर ग्राउण्ड होकर आया हुआ है। बेसिकली उसको पीछे से जाने की बात थी लेकिन यहां के लोगों के द्वारा बी०ओ०डी० के द्वारा उनको ये परमिशन दे दिया गया कि तुम हमारे को-ऑपरेटिव से लेकर जाओ। तो हमलोग एक बहुत बड़े बम पर बैठे हुए हैं और इस बिन्दु पर विचार करना है। अभी जो एक गेट खुलता है जिसे हमलोग राजमार्ग कहते हैं जो डी०पी०एस० के तरफ जाता है और जो हमलोग का चार नम्बर मेन रोड खुलता है दूसरे मेन रोड पर जाता है वो गेट बन्द है और उसके गेट पर पूरा केबल गिराये हुए है बिजली बोर्ड, कोई कग्नीजेंस नहीं है उसका। लगता है वहां उस गेट का उस एरिया का कोई मालिक ही नहीं है। मार्निंग वाक में आप अगर वहां जायेंगे तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये थर्ड पार्टी यहां का कराता है उसने कहा कि जैसा है हम एज इट इज कर देंगे लेकिन ये लोग करते नहीं हैं और जितने भी लोग हैं वो कहते हैं कि यहां थर्ड पार्टी में यहां लोकल भेंडर्स को रखते हैं और वो यहां आकर दादागिरी करते हैं। इसी क्रम में हम पूछे तो वो बोले कि चीफ इंजीनियर एलाउ किये हुए हैं। जो जी०एम० इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड हैं हमने उनको बुलाया फिर अरगोड़ा थाना को बुलाया फिर उसके बाद बिजली बोर्ड के सारे लोग आये, सबने कहा कि हमने कोई परमिशन इसको नहीं दिया है। न हमने गेल को परमिशन दिया है न वाटर सप्लाय



वाले को परमिशन दिया है। हमलोग मॉर्निंग वाक करते हैं, देखते रहते हैं, उनलोगों को रोकते हैं कि भाई तुम रुको लेकिन वो लोग रुकते नहीं हैं। तो मान लिया जाय कहीं पेभर लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है वो सब को वो डिस्ट्रॉय करते हैं। आज ही हमलोग मॉर्निंग वाक में देखे कि अभी यहीं पर सामने रोड को उसने पूरा खत्म कर दिया। तो आखिर जो ये रोड बी०ओ०डी० के पैसे से बनता है और अभी कुछ ही दिन साल-दो साल पहले ये रोड बना था तो फिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेते हैं? कौन बनवायेंगे इसको, ये किसका पैसा जायेगा, हम ही लोगों का पैसा जाएगा। इसी प्रकार से देखा जाय जब हमने इसका विरोध किया था तो पी०पी० शर्मा साहब का जो कॉर्नर है वहां पर 11 के०भी०ए० का केबुल और पानी सप्लाई वाला लाईन दोनों साथ-साथ गया हुआ है, अभी भी वहां चेम्बर बना हुआ है। उसको बी०ओ०डी० जाकर देख सकते हैं कि इस तरह का डेंजरस काम क्यों। कल को आपका मिस्ट्री वहां काम करने जाएगा और वो मर जाएगा, तो इन सब बिन्दुओं को देखना होगा। आप थर्ड पार्टी को लगा देते हैं वो कहेंगे कि मेरा सेटिंग है हमको काम करने दीजिए और काम भी हो जाता तो ये उचित बात नहीं है हमारे समझ से। इसका एक रोडमैप तैयार होना चाहिए और उस रोड मैप में ये रहना चाहिए कि अगर 33 के०भी०ए० का केबलिंग हुआ है तो कैसे हुआ है। ये जिम्मेवारी बिजली बोर्ड की बनती है। बिजली बोर्ड से कभी किसी ने इस चीज को नहीं माना। जो वाटर सप्लाई वाले है उसमें जिंदल साहब ठेकेदार हैं वो थर्ड पार्टी को दिये हुए हैं उनका कोई नक्सा नहीं है। इसी तरह से गेल वालों का कोई नक्सा नहीं है। सबरे 25-50 मजदूर उठते हैं और जहां का मन होता है वहां का रोड खोद देते हैं और लोग गिरते रहते हैं। ये सब होता रहता है। तो इसके लिए यहां एक टीम होनी चाहिए बी०ओ०डी० में जो उसकी निगरानी करे, उसको देखे और बार-बार कहते हैं कि ऐज इट इज जैसा है हम बना देंगे लेकिन वो बनाते नहीं हैं ऐसे ही छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी हैं, ठेकेदार हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि बराबर रेवेन्यू की बात होती है और बी०ओ०डी० देखे इसको कि जितने सारे पोल हैं उसमें कम से कम 100 केबल्स टंगे हुए हैं। वो या तो जीओ के हैं या तो रिलायंस के हैं या अदर जो भी हों। वाईफाई सिस्टम वाले हों सबों का बॉक्स वगैरह लगा हुआ है, सारे घर से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो अशोक



नगर को-ऑपरेटिव को रेवेन्यू देते हैं? अगर नहीं देते हैं क्यों नहीं देते हैं उनका लाईन हमलोग काट दें। हमको भी तो रेवेन्यू मिलना चाहिए। वो भी कमा रहे हैं तो अशोक नगर सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाईटी की जमीन्दारी में वो कर रहे हैं तो हमको भी मिलना चाहिए न, अशोक नगर सोसाईटी को मिलना चाहिए। अभी जैसे गैस का है, रिलायंस का एक टावर लगता है तो हर महीने 80 हजार रू० वो पेमेंट करता है जिनके भी जमीन में लगता है। ये गैस ऑथोरिटी आफ इंडिया वाले बड़े-बड़े लगा दिये हैं और उसका पैसा वो देते हैं कि नहीं देते हैं इसको बी०ओ०डी० देखे। इतनी जमीन दिये हैं तो गैस का पैसा हमसे क्यों लेंगे, बाकी मेम्बर्स से क्यों लेंगे? आपको अगर देते हैं तो अच्छी बात है नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं माल पैकिटश है जिसके चलते शुरू से जो भी हुआ होगा वो हुआ होगा। तो ये पैसा उनसे वसूला जाना चाहिए कि लाईये आप ०१ लाख रू० दीजिए हमारी जमीन का। सलाना १२ लाख हुआ १२ लाख रू० से हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। अब हम बहुत समय नहीं लेंगे और अन्त में चेयरमेन साहब को साधुवाद देना चाहेंगे कि जो इन्होंने पेभर के लिए उसके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लगकर झारखण्ड सरकार से कराया है इसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं माननीय सांसद श्री दीपक प्रकाश जी को भी धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मन्दिर के सौंदर्यीकरण इत्यादि में पैसा दिया है और वो विकास का काम चल रहा है और विशेष रूप से उस मन्दिर के कार्य के लिए मुकेश बाबू ने प्रयास किया और वो पैसा आया। आज के डेट में मन्दिर का हमारा अच्छा गेट बन रहा है सबकुछ बन रहा है और मैं चेयरमेन साहब से अनुरोध करूंगा कि ये तो मेरा को-ऑपरेटिव का पैसा है, जो हमारा आउटसोर्सिंग है, जिसपर मेरा अधिकार है, करोड़ो-करोड़ रूपया हमलोग नगर निगम का देते हैं, नगर निगम से हमलोग पैसा लें, उसकी सुविधा वो देने के लिए तैयार है हम याचक ही नहीं रहेंगे तो हमें वो देगा कहां से। अभी जैसे बहुत अच्छी बात अध्यक्ष ने कहा ५० लाईट आ गया है। ५० लाईट में २० लाईट हमलोग लगवा चुके हैं ३० लाईट बाकी है वो २० लाईट कहां-कहां लगा, किस-किस एरिया में लगा? तो सबों का ध्यान दिया जाए और सबों को देखा जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे सुझाव को लिखा जाए और लिखकर जैसे गेल

से है या जीओ से हैं या जितने केबुल वाले हैं, सबों से पैसा लिया जाय जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़े और जो भी इस तरह के काम हमारे को-ऑपरेटिव में होते हैं उसके लिए बीओडी जरूर उनसे पैसा मांगे। अदर वाईज ये कहते रहने से और करते रहने से कोई अन्तर पड़ने को नहीं। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

9. श्री प्रदीप कुमार, 77/डी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निदेशक मण्डल और हमारे साथीगण, आप सबों का बहुत-बहुत अभिनन्दन। मुझे मौका मिला है बोलने का, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि दिनांक-30.04.2023 को जो बैठक हुई थी क्लब से संबंधित, उसमें उसकी कार्यवाही की सम्पुष्टि के लिए एक अनुपालन प्रतिवेदन आया है जिसमें ये लिखा गया है कि आई0ए0 कोर्ट में फाईल की जायेगी। यहाँ के निदेशक मण्डल के श्री प्रताप कुमार सिंह ने ऑलरेड्डी एक आई0ए0 फाईल कर दिया है और मुझे यह भी जानकारी है कि शायद बीओडी द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं दी गई है और इसकी सम्पुष्टि के लिए यहाँ पर लाई गई है। मैं ए0जी0एम0 से पुनः अनुरोध करूंगा कि की कृपया इस कार्यवाही की सम्पुष्टि न की जाय। तत्पश्चात् मैं जो बजट है उसके उपर आता हूँ। बजट के ऑडिट रिपोर्ट को देखा जाएगा तो उसमें ऑडिटर का रिपोर्ट संलग्न नहीं है। दूसरा, इसमें ऑडिटर ने दिया है कि हमारा रिजर्व फंड रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू 2012 से 60 परसेंट रिजर्व फंड रेवेन्यू में डाला जाता था और कैपिटल रेवेन्यू में 40 परसेंट डाला जाता था। इसका उल्लेख 2012 के ए0जी0एम0 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जो भी जमीन ट्रांसफर होती है उससे जो आमदनी होती है उसका 60 परसेंट हमारा रिजर्व फंड हुआ और 40 परसेंट हमारा कैपिटल रेवेन्यू हुआ। ये दोनो इस ऑडिट रिपोर्ट में नहीं है और ना ही बजट में है। इसमें एक स्पष्ट रूप से दिया हुआ है बजट में दिखाया गया है कि 76,000/- रूपया बीओडी के एक्सपेंस में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि 76,000/- रूपया एक्सपेंस ऑन बीओडी और 2022-23 के बजट में इस एक्सपेंस को ऑनरेनियम में लिया गया। रिपोर्ट के 35 नम्बर पेज में लिखा हुआ है कि एक्सपेंस ऑन बीओडी। ये ऑडिटर ने ऑडिट किया और 2022-23 का जो बजट आप लेकर आये हैं उसमें

आप दिखा रहे हैं कि एक्सपेंस ऑन ऑनरेनियम 76,000/- रूपया और इसकी आप घटनोत्तर स्वीकृति मांग रहे हैं। ऑनरेनियम किसे दी जाती है? हम सभी लोग जानते हैं कि ऑनरेनियम क्लास थ्री और क्लास फोर के लोगों को दिया जाता रहा है और सरकारी प्रक्रिया यही है कि साल के अन्त में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको प्रशस्ति पत्र दी जाती है। ये ऑलरेड्डी बजट में दो-दो लाख, तीन-तीन लाख रूपया का जो प्रोभीजन किया हुआ है ये नहीं होना चाहिए, इसमें संसोधन कर दिया जाय। ऐसा नहीं है कि हम इसके अगेंस्ट में हैं लेकिन इसमें संसोधन कर दीजिए। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि इसमें दिया हुआ है एक्सपेंस ऑन बी0ओ0डी0, ये क्या है? आगे मैं 2023-24 के बजट पर आता हूँ। बजट में दिखाया गया है कि इसमें सैलरीज ऑफ रेगुलर स्टॉफ का 30 लाख है जबकि गत् वर्ष खर्च हुआ था 22 लाख। इसमें 08 लाख की बढ़ोतरी हुई है। डेली वेजेज में 70 लाख है जबकि गत् वर्ष 42 लाख खर्च हुआ था इसमें लगभग 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है। कहने का मतलब है कि 01 करोड़ रू0 केवल रेगुलर स्टॉफ और डेली वेजेज के लिए है। यानी कुल मिलाकर 40 लाख रूपये की बढ़ोतरी हुई है। कंटीजेंट एक्सपेंसेस में 50 लाख रूपया रखा गया है। सिक्यूरिटी स्टॉफ सैलरी (एस0आई0एस0 लि0) में 50 लाख रूपया रखा गया है। इसमें आप एस0आई0एसव लिमिटेड को भुगतान कर रहे है या सिक्यूरिटी स्टॉफ सैलरी के लिए है ये बहुत मेजर विषय है ए0जी0एम0 के सामने। इसमें एक चीज क्लियर कर दिया जाय कि एस0आई0एस0 को कंटीन्यू करना है या दूसरा एजेंसी को बुलाना है। आपसे अनुरोध होगा कि इसको आप स्पष्ट करें कि एस0आई0एस0 को करेंगे कि किसी दूसरे को। इसपर हमारे बहुत से सदस्य एग्री नहीं हैं। कंटीजेंट एक्सपेंसेज में बहुत सारे चीजों को मर्ज कर दिया गया है इसमें हमारा कहना है कि पहले जैसे था वैसे ही कीजिए। वाटर सप्लाई और इन सबों के लिए आपसे अनुरोध है कि पार्क सी में एक सम्प बनाईये। पार्क सी जो सबसे हाईयेस्ट जोन है वहां पर आप एक सम्प बनायें, उसमें आप पानी लें उससे आपका चार नम्बर रोड से लेकर मन्दिर मार्ग तक पानी का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जायेगा। कुछ मर्दों में कटौती करके आप सम्प बनाने के प्रस्ताव को 59 वें ए0जी0एम0 में किया गया था कि एक सम्प बनाया जायेगा पार्क डी में। यदि पार्क डी में आप नहीं बना सकते हैं तो आप पार्क सी में

बनाईये। सम्प बन जाने से हमारा जो पानी का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जायेगा। कुछ मदों में कमी लाकर इस काम को किया जाना चाहिए। हमारा ये कथन है कि जो जुडको पानी की सप्लाई कर रही है उसके अलावा भी कुछ व्यवस्था रहनी चाहिए क्योंकि हमलोग देख रहे हैं कि पी0एच0ई0डी0 कितना पानी सप्लाई कर रहा है। हमारी सोसाईटी की व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए ये जरूरी है कि हम बराबर सर्वे करें। मैं आपको सूचना के लिए बता दूँ कि मैं खुद एक इंजीनियरिंग से रिटायर आदमी हूँ। मैंने कई बार यहां के इंजीनियर को कहा कि कोई भी ऐसा मशीन लाओ जिससे हम लेबल ले सकते हैं। हम खुद गाईड कर देते कि कौन से लेबल में पानी कैसे जायेगा तो वो नहीं ला सके। हमारे सोसाईटी में 15-20 हजार रुपये का एक लेबल मशीन भी नहीं है जिससे आदमी लेबल ले सके और काम कर सके। यहां का एक ज्वलंत मुद्दा है कि हमलोग का म्यूटेशन नहीं हुआ। रोड के किनारे जितने लोग हैं उनकी 25 फीट जमीन जा रही है। उसमें हमलोग कुछ नहीं करेंगे सरकारी जमीन ले रही है। सरकार उसको लेकर रोड का चौड़ीकरण करने जा रही है और उनका कोई क्लेम नहीं बनेगा जबतक उनके पास म्यूटेशन नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति हो गई है कि न विलेज मैप है, न विलेज मैप के उपर हमारा अशोक नगर का ओभर मैप करके बनाया हुआ है। इन सब कामों के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आप अप्वाइंट कीजिए। वो लोग आपको बनाकर देंगे कि कौन से विलेज मैप में क्या है। अगर आपको इसका आईडिया नहीं है तो हम आपको इसमें मदद कर देंगे। यहीं कॉलनी में ये सारे लोग हैं और उनकी ऑफिस भी है इसी कॉलनी में, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। हमलोग को टेक्निकली थोड़ा साउंट होना पड़ेगा तब हमलोग आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि बजट में आवश्यक सुधार कर लिया जाय इसके बाद लाया जाय। बजट के विरोध में मैं नहीं हूँ। बजट में कुछ आवश्यक सुधार चाहता हूँ।

10. श्री बसन्त प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, निदेशक मण्डल के सदस्यगण और यहां उपस्थिति सभी लोगों का अभिनन्दन करता हूँ। मैं बसन्त प्रकाश, मैं लिखित सुझाव लाया हूँ क्योंकि मिनट्स ऑफ द मिटिंग में जिस तरह से हमारा स्टेटमेंट दर्ज था वो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। बीच के प्वाइंट

गायब कर दिये गये थे। इसलिए मैं आज लिखकर लाया हूं। मैं अपना साईन करके आपको दे भी दूंगा। जिससे कि उसमें एडिटिंग करने का कोई गुंजाईस न हो। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि इस बार ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही है। सचिव जी, बतायें।

अ0सचिव : ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है।

श्री बसन्त प्रकाश : ठीक है।

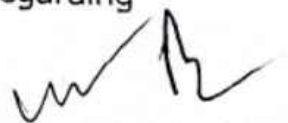
1- Page no 11 My statement recorded by the board. I had asked the general body to give their approval to the following point:

"Henceforthe the Board shall not have any right to sell,lease,mortgage even a sq. Inch of land without the approval of AGM."

I remember there was a unanimous approval for this statement. This statement has been deliberately deleted if the Board has any doubt I will request them to play the audio video recording right now in the presence of general Body and get satisfied.

2- Slow progress with regard to mutation of land is worrisome. The Board must explain about obstructions they are facing. Why Board is hesitant to take support of other members. They must take the entire society in confidence by interacting with them on daily basis thru whatsapp group. I do hope members in good numbers will come forward to help the Board in this matter. Each and every member is worried and I do request the board to understand the gravity of the situation.

3- The chairman's statement recorded has one objectionable comment that is going to be recipe for the superseding of the board by the authorities. Please ref page 26,Line 7 " न तो इस बोर्ड को एक ईंच बेचने का अधिकार है । न ए0जी0एम0 को जमीन बेचने का अधिकार है । Unfortunately the Chairman's statement is in contradiction of our Bye Laws Clause 43,44 and vivid ,explicit 44(iv) which gives absolute power to the board to do transactions regarding land.



Water supply related problem being faced by the members of Mandir Marg.
Water supply related issue affecting the members of Mandir Marg. Water
supply related issue affecting the members of Mandir Marg.

It is to inform that plot no.98-C has not received water supply from Ashoknagar Society since April 2023. All the residents of this locality will agree with me that they are also facing water crisis more or less along the same period. Despite several complaints the Society has not taken up the issue seriously at all. Severe infighting within the Board Members has aggravated the problem. Unfortunately it seems none of them are bothered and it is evident that this issue is frivolous for them as in the aforesaid period the Board has taken up several works which were not urgent in nature eg laying of paver blocks, Installation of gates, concretization of natural drains with approximately 18 inches cover thickness

1. SEVERAL COMPLAINTS LODGED BY THE MEMBERS OF THIS LOCALITY
IGNORED BY THE BOARD

2. ONE TO ONE MEETING WITH CHAIRMAN AND SECRETARY HELD ON
29TH MAY - NO RESULT

3. ONE TO ONE MEETING WITH CHAIRMAN HELD ON 29TH JULY 2023
ENDED WITH ONLY

ASSURANCE OF A DEEP BORING WITHIN A WEEK. NOTHING DONE SO FAR

Now we don't want any assurance Instead we want following actions:

a. A DEEP BOREWELL IN THE AREA TO CATER TO THE AFFECTED HOUSES
WITHIN A WEEK

b. WHY THIS AREA IS BEING DENIED THE ACCESS TO PHED WATER. WE
ARE PAYING THE WATER SURCHARGE THRU THE BOARD EACH AND EVERY
YEAR. 1.5 LAC GALLON LEERE WATER IS BEING RECEIVED BY THE SOCIETY
EVERY DAY SUPPLIED BY PHED.

WE WANT A WATER TOWER IN THE VICINITY OF THIS LOCALITY THRU WHICH PHED WATER COULD BE SUPPLIED TO THIS AREA.

(THE IDEAL LOCATIONS - THE PHED CAMPUS ON ROAD NO.1 OR ABUNDANT LAND IN PARK C)

C. Enhancement in budget allocation of Rs. 10Lacs to at least Rs.1 crore curtailing the contingency expenditure.

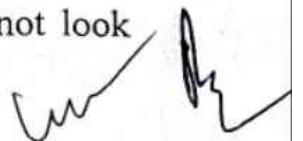
11. श्री रवि शंकर सिन्हा, 491 : अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय आपलोगों ने मुझे बोलने का मौका दिये इसके लिए आपलोग का हम शुक्रगुजार हैं। हम तो चाहेंगे कि बहुत अच्छे माहौल में मिटिंग हो और वर्मा साहब बहुत चीज बोल दिये हैं इसलिए हमलोग को बोलने के लिए अब कुछ खास नहीं है। मैं रविशंकर सिन्हा 491 से आता हूँ। मेरा एक अनुरोध है कि आप मेरा गेट नहीं खोल सकते हैं घर में जाने के लिए। मेरे गेट पर कम से कम 10 से 20 गाड़ियाँ लगी रहती हैं। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि अभी नगर निगम ने अपना बाउंड्री मार्क कर लिया है हमारा जो 06 नम्बर गेट है आप वहां शिफ्ट कर दें और सिक्यूरिटी की व्यवस्था वहां से हटाकर आप मेरे पास कर दें सो दैट उसमें कम से कम कनविनीयेंट होगा जो आउटसाईडर हैं वहीं पर रूक जायेंगे और कुछ कारण से मेरे गेट पर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं घर में जाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए कम से कम एक घंटा का समय मुझे लगता है। जब मैं गाड़ी निकालना चाहता हूँ तो मुझे एक से डेढ़ घंटा का समय लगता है। दूसरा एक छोटा सा अनुरोध है अभी आपने बताया कि 50 लाईट आया है जिसमें 20 लाईट लग गया है बाकी जो 30 लगना है उसमें अरगोड़ा चौक में कम से कम जो मेरे घर के पास पोल है वहां पर एक लाईट लगवा दिया जाता तो हम बहुत कृतज्ञ होते। दूसरी बात सचिव महोदय, मैंने कभी नहीं बोला था कि बाहर आउटसाईडर से सिक्यूरिटी चार्ज लिया जाय। आपने बताया था कि आउटसाईडर जो हैं वो सिक्यूरिटी चार्ज नहीं दे रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं अपना चार्ज देता हूँ तो आप खुद बोले कि इसको वापस कर दिया जायेगा आपको। इसको सुधार की आवश्यकता है जो इसमें लिखा गया है। लेकिन आगे से मुझसे नहीं लेने के लिए एक दिया जाय। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था

सचिव महोदय से तो बोले की आप एक अप्लीकेशन दे दीजिए बोर्ड में इसपर कंसीडरेशन होगा। मैं तो दे दिया हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चलते और भी जो आउटसाईडर हैं वो भुगतें। मैं ऐसा भुगत नहीं चाहता हूँ। बजट में एक बड़ी बात है कि आपने कंटीजेंसी में काफी अमाउन्ट रखा है। हमलोग कम से कम 35 साल नौकरी किये कंटीजेंसी का एमाउन्ट हमलोग के यहाँ सबसे कम होता था। प्रोजेक्ट का जो भी होता था उसका 05 परसेंट ही प्रोभीजन रखते थे तो एक अनुरोध होगा कि कंटीजेंसी जो आप, सब हमलोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो कंटीजेंट एमाउन्ट उतना रखिये जो स्टीमेट का 05 परसेंट हो या 04 परसेंट हो। So That की उसमें दिक्कत होगा। दूसरा एक है कि आपने 01 करोड़ रू० खर्चा करने का किया है जिसमें से आप 50 लाख रू०, 13 नम्बर सीरियल पर देखा जाय इसमें आपने 50 लाख ऑलरेड्डी खर्चा कर दिया है। 50 लाख खर्चा कैसे हुआ और क्यों हुआ इसका एक विवरण चाहिए था सर। आपने डेली वेजेज के लिए पिछले साल 42 लाख खर्चा किया था अभी 70 लाख का प्रावधान है। तो जब हमलोग सोसाईटी से नगर निगम को इतना पैसा देते हैं तो इस सारे व्यवस्था को ठीक करने के लिए उनपर प्रेशर डाला जाय और कडरू एक कॉलनी है, छोटा सा कॉलनी है, जिसमें जायेंगे तो हमारे से अच्छा उनका रोड भी है, हमसे अच्छा उनका साफ-सफाई भी है, तो क्यों हमारे यहाँ नहीं। अशोक नगर में काफी लोग हैं जो आई०ए०एस०, आई०पी०एस० रहे हैं और अध्यक्ष महोदय खुद भी रहे हैं इसमें तो मेरा अनुरोध होगा कि उससे व्यक्तिगत अनुरोध किया जाय ताकि हमारे सोसाईटी को भी अच्छा से अच्छा बनाया जाय। तो सर थोड़ा लाईटर मोड में आपलोग बहुत परेशान हुए हैं इसलिए हमारे तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनायें। आप इसी तरह से इन्जॉय कीजिए मेरा यही कहना है।

12. श्री अरविन्द कुमार, 181/सी : दूसरे सेशन ऑफ ए०जी०एम० में जो चर्चा हो रही है 2022-23 के बजट में ये क्यों नहीं चर्चा हुई। 2022-23 के बजट में जो 5-6 करोड़ का बजट था उसमें 50 परसेंट खर्च नहीं हुए और उसमें कोई माईक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं हुई चूँकि वो बजट एबेंडेंट था वो पैसे ऐसे ही रह गये किसी ने उसको हड़प नहीं लिया। हमारा यही कहना है कि आज आप

जो देख रहे हैं कि बोर्ड के सामने कुछ डिफिसियेंसी है, ये डिफिसियेंसी बोर्ड पार्टीकुलर के कारण नहीं है ये सदस्यों के कारण है। सदस्यों के इनडिफ्रेंस के कारण है। प्रयास हो रहा है इसको करेक्ट करने के लिए प्रयास हो रहा है और जिस तरह से वर्मा साहब ने जो ये किया है ये करना चाहिए लेकिन ये जो इन्टरनल प्रोब्लम है सोसाईटी का, सोसाईटी के बोर्ड के साथ, सोसाईटी के सुविधाओं के साथ उसके अलावे एक्सटरनल प्रोब्लम है। इस कंट्री में जैसे सिर्फ कंट्री के अन्तर्गत हमलोग एक राज्य नहीं आता एक बाउन्ड्री भी आता है वैसे ही सोसाईटी के मामले में एक बाउन्ड्री भी आता है। आज हमलोग देश में अमृतकाल मना रहे हैं इस सोसाईटी में इस बोर्ड के द्वारा जो काम किये गये हैं जिसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पहला, थाना बिल्डिंग, थाना बिल्डिंग के काम को क्यों नहीं दूसरे बोर्ड के लोग किये? क्योंकि दूसरे बोर्ड ये करते तो कानून के तहत जाते, एस0डी0ओ0 के यहाँ जाते, ये करवाते, वो करवाते, लेकिन इस बोर्ड में जो एक अलग कैरेक्टरिस्ट कहिये या जो भी उतावलापन है ये लोग उठे पुठे और जो नाजायज तरीके से रह रहा था तो ये जो है वो एक चीज, दूसरी चीज जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ है वो झिरी में ट्रैक्टर से सब ले जाने का उससे जो हमको आजादी मिली है वो आजादी का अमृतकाल है सोसाईटी के लिए। अगर हम उसको परसीभ नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो जितने टेक्निकल बातें हैं, आज आपको कहें न कि 2022-23 में जो बजट पास किया, एक्सपेंडिचर का डबल बजट पास किया, ड्यूरिंग तक खर्च कोई आदमी माईक्रोस्कोप लेकर नहीं गया लेकिन हॉफ ऑफ द बजट रिमेंड बाई सच। इसलिए हम जो माईक्रोस्कोपिक एक्जामनिसंस की बात जो किये हैं ये होनी चाहिए लेकिन मैं इस सोसाईटी के सदस्यों को पुनः कहना चाहूंगा कि ये कोई सरकारी विभाग नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, ये को-ऑपरेटिव सोसाईटी है, को-ऑपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत जो इसका स्पीट है कि जो मेम्बर लोग हैं, उनके बीच जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अपना चलायें। हमारा जो कहना है कि इस सोसाईटी के साथ जो बाउन्ड्री है, बाउन्ड्री से जो प्रॉब्लम आ रहा है एक भी मेम्बर को कोई मतलब नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि जो सात सदस्य जिनको 25 करोड़ का नोटिश दिया गया है ये उनका प्रॉब्लम है? आज दस साल के बाद, बीस साल के बाद ये 100 करोड़

आयेगा और ये जो है असली लाईबिलिटीज सोसाईटी का है। आप कहां से देंगे? लेकिन किसी को ये मतलब नहीं है कि इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति क्या है। अब इसमें कुछ भी चेंज होगा, जो भी होगा बिना कोर्ट के इन्फोल्डमेंट का नहीं होगा और हम तो यही कहते हैं कि जो सरकारी विभाग का जो अनुभव लेकर आये हैं वो भोलेंटियर करें कि इस मामले में वो जो सात सदस्य हैं वो हमारे पार्ट हैं। हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और उनको छोड़ दिया। हम तो आज बोलना भी नहीं चाहते थे कि ऐसे ए0जी0एम0 के मिटिंग में बोलकर क्या होगा जो सात सदस्यों के बारे में जो कब रोड पर आ जायेंगे उनका क्या? कल जोगिन्दर बाबू से बात हुई He is more than 90 years old. He was so much concern लेकिन किसी के मुँह से उसकी चर्चा नहीं आती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो कंप्लायंस करना था सोसाईटी को उसके अगेंस्ट में जो कंप्लायंस नहीं हुआ उसके अगेंस्ट में हाउसिंग बोर्ड कंटेट ऑफ कोर्ट में गया था। कंटेट ऑफ कोर्ट में जो सोसाईटी के द्वारा रिप्लाय दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि एक्चुअली हमने एक अलग रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर किया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि ये कट ऑफ ईयर 1993 हो। साहब कोई तो भोलेंटियर कीजिए हमलोग कर्मठ लोग हैं ये सोसाईटी का प्रॉब्लम है। कल ये चीज 100 करोड़, 200 करोड़ होगा तो एक नोटिश आयेगा कि सोसाईटी के एसेट को निलाम करो। इसलिए मेरा ये कहना है कि आज आप जो बोर्ड की बात कह रहे हैं कि बोर्ड ये नहीं किया, वो नहीं किया, आज बजट के बारे में कह रहे हैं, आपका तो गलत बजट पारित किया गया इसी ए0जी0एम0 से 2022-23 का आपलोग कोई नहीं देखने गये। मैं इस ए0जी0एम0 को देख रहा हूँ 12-13 साल से जब से रिटायर किया हूँ कि क्या एजेंडा है, इसमें क्या डिस्कशन हुआ है, इमेन बाई-लॉज के अमेंडमेंट पर, आप जो कोरम की बात कह रहे हैं न उसमें क्या है कि को-ऑपरेटिव एक्ट के तहत आपने इसमें अमेंडमेंट नहीं किया, आप तो ऐसा अमेंडमेंट नहीं किया है कि एक आदमी अगर मेम्बर बनने के लिए योग्य है वो अप्लीकेशन देगा तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं और इसी कारण से आपके सोसाईटी को सस्पेंड कर दिया और इतने दिन से तो अमेंडमेंट हो रहे हैं, इतने अमेंडमेंट हुए But that was not look



in twit. इसलिए हमारा यही कहना है अगेन कि हमलोग सरकारी कर्मचारी है सरकारी डिपार्टमेंट के बड़े-बड़े पद पर रहे हैं लेकिन उसी नजरिये से अगर आप सोसाईटी को देखियेगा **It is a society, it is not a department.** ठीक है ऑडिट होता है लेकिन आप लिभरेज नहीं दीजिएगा तो आपका ये सोसाईटी नहीं चलेगा। मैं एक पार्टीकुलर बात बता रहा हूं इसलिए हमलोगों को बाहर से जो प्रॉब्लम है, एक तो इनलोगों ने बहुत बड़ा काम किया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इन्भॉल्ब किया है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इन्भॉल्ब करके जो क्लिनलेश का जो प्रॉब्लम था उसको बहुत हद तक इनलोगों ने सॉल्व कर दिया। इसलिए हमारा कहना है वर्मा साहब का जिस तरह से कर्मठता है लोगों में आये लेकिन सोसाईटी के साथ और इश्यूज हैं सोसाईटी के लोगों को एजुकेट कीजिए, सोसाईटी के मेम्बर को एजुकेट कीजिए इन्भॉल्बमेंट के लिए और हाउसिंग बोर्ड के साथ 25 करोड़ का जो मामला है उसमें भौलेंटियर कीजिए कि कैसे हम आगे बढ़कर इस मामले को जो सात सदस्य हैं इनका क्या फॉल्ट था। लेकिन वाह रे ए0जी0एम0 किसी को कोई मतलब नहीं है। अपना-अपना राग, अपना-अपना गेट, अपना-अपना मोहल्ला। धन्यवाद।

13. P.K Sahay -461/A

I personally feel that they also deserve bouquet for good work done by them for example recently they involved the municipal corporation and have got sanctioned for laying of pavers and also for lighting so this is really a good job done and in future also we should try to involve more and more Ranchi Municipal Corporation to undertake developmental work inside the colony for example the upkeep the lighting given the water supply since were paying holding tax to them so it is their ability to provide these services that only thing is



to be have to interact with and liaise with them and also get their support in future .

I have flaying 3-2 issue a lot of discussion is already taken place but the first issue is mutation when the elections were held last time this was high on the Agenda of elected office bearers and they have promises was that deal with this will be expedited but in the report which has been circulated is it is mentioned that slow-slow work in progress and they are Technical difficulties in the way so

I will I would like to request the chairman to lighten the house on the Technical difficulties which they are facing because as you are aware in the master plan of Ranchi Dala-dali Road has to be widen and about 20 feet of land the plot holders on the dala-dali road will be losing and is this amounts to almost three or four decimal of land and as you are aware for proper recognition of say ownership mutation is a must,

otherwise the payment of compensation will lead to legal complications. So I feel that this should be fast track .

incidentally I may mention that the Patliputra Colony Patna also came into existence at the same time as this colony and their the mutation was a long time back so this should be fast track.

the second issue is water supply I shifted to this colony in the year 2020 and in fact 3-4 days, there was no water supply there was some breakdown and Mr. Podder told me that some bearing and some part is to be replaced and that is not readily available.

So I personally feel that the water supply system here is very old and it should be revamped. Audit of water the supply system should be done and if some deficiency are found in a revamping plan should be prepared and in the proposed budget for 23 -24 also as one member has already mentioned that only 10 lakh savinay located this appears to be inadequate and show the funds if required from the general maintenance activities like Paver, Road and lighting convert repair, maybe it will have to be relocated and so this needs relook the amount of 10 lakh which has been allocated and finally the domestic supply, domestic gas supplied by Gail so this work is being done by a Gail, but I think it is been done by very unprofessional and have hazard manner, and I would like to know you if someone has been signed with the society and if you are time frames in it was example when they will complete the laying of Gas pipe lines and what is the time frame for providing the connection in the house once they member has deposited the installation money and the precaution money So when one of the representatives will hear I interacted with him. And I found that it will be done

within he said that it will be done within 24 hours, but many people have deposited the money but this job has not been done for months together so need this relook .

and one final point normally when we Award some work to the contractors they also sub- contract it and we have got very little control over its subcontractors actually in every contract it is a standard clause and if the road has been disturbed and some digging has been done then it must be restored to the original condition before the bills are clear. this should be enforced, we should try to enforce it.

Thank you.

अ० सचिव : वरीष्ठ सदस्यों से अनुरोध है कि बजट को पास किया जाय।

(इस अवसर पर ध्वनीमत से बजट पास किया गया)

अ० सचिव : धन्यवाद। अब अध्यक्ष महोदय अपना वक्तव्य देंगे।

डॉ० माधव, अध्यक्ष : हम दो तीन बिन्दु क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं कि जो सदस्य हैं उनको स्वभाविक रूप से लगता होगा कि कंटीजेंट में 50 लाख क्यों है। कंटीजेंट में 50 लाख नहीं है। वो कंटीजेंट जो हमारे ऑफिस वाले कंसेप्ट में है क्योंकि यहाँ कई छोटे-छोटे हेड थे 04 लाख, 05 लाख 06 लाख, वो काफी बड़ा एमाउन्ट होता था बहुत हेड हो गया था। उस कंटीजेंट हेड में जैसे फिनाईल खरीदना है, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना है, पाईप को थोड़ा कुछ करना है और इस बार क्यों बढ़ा हुआ है ये जानना चाहिए 15 लाख रू० होल्डिंग टैक्स आपको जमा करना है। 2022-23 का शॉपिंग कम्प्लेक्स का। ये सोसाईटी ही देती रही है तय करना है ए०जी०एम० को। उसमें 03 लाख के करीब पेनाल्टी है। इसलिए उसको कंटीजेंट में डाले कि ये तो हर दिन का नहीं होगा तो

कंटीजेंट उसमें डालकर 15 लाख रूपया हमको कल से परसो तक में डालना होगा इस बजट के बाद ये आपको जान लें। शॉपिंग कम्प्लेक्स का कितना किराया आता है पिछली दफा कहा गया है लेकिन इसपर किसी ने विचार नहीं दिया कि इसका क्या करना चाहिए। इंडीविजुअल पाईप के लिए, पानी के लिए, लाईन के लिए वो स्वभाविक है हर आदमी इंडीभ्यूजुअल काम करेगा लेकिन जो कॉमन सोसाईटी का दो-तीन वर्क है, म्यूटेशन, 08 प्लॉट के बारे में अरविन्द बाबू ने एक्सप्लेन किया। दी देन बोर्ड ने भी कई बार पत्राचार किया है हाउसिंग बोर्ड को। उसके पहले के आर0आर0 प्रसाद ने भी किया है जो बहुत अच्छी चिट्ठी थी लेकिन चूँकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमलोग की जो कमियां हैं कि हम भी वही कर रहे हैं, पत्राचार में हम इसको उलझाये हुए हैं। इनलोगों ने भी पत्र लिखा, हम भी पत्र लिख रहे हैं। पत्र से उलझेगा मामला। दो चीज आपलोग को बता दें क्योंकि यहाँ सब लोग सरकारी लोग हैं। अगर सरकारी जमीन है तो उसके लिए एभिकशन सूट नहीं होता है। अगर सरकारी जमीन को कोई इन्क्रोच करता है तो उसके लिए नोटिश देगा और आपको डिमोलिश कर देगा। इस बात को सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपलोग देखे होंगे। अगर कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है, दूसरे तरह का इन्क्रोच होता है तो उसमें एडीक्शन सूट, एस0डी0ओ0 कोर्ट, नोटिश बहुत सारे प्रोसेस हैं लेकिन जो प्योर गवर्नमेंट लैंड है सरकार कहती है कि ये मेरा लैंड हो तो आपको एक नोटिश देगी और आपको ध्वस्त कर देगी। आप कुछ नहीं कर पाईयेगा आपको न हाईकोर्ट मदद करेगी, न सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। लेकिन हमलोग इसपर लगे हुए हैं, हमलोगों ने एक पत्र दिया है, हमने अनुरोध किया है एम0डी0 से कि हमलोग एक साथ बैठें सारे कागजातों को देखें और इसका एक सॉल्यूसन निकले। लेकिन वो तो गवर्नमेंट के लोग हैं जब तक हमलोगों को बुलाते नहीं हैं समाधान कैसे निकलेगा। हम हर बार लिख रहे हैं ताकि कल अगर हमारे उन 7-8 मेम्बर को कोर्ट जाना पड़े तो हम एक डिफेंस ले सकें। हम अपनी ओर से रिलैक्स नहीं हैं हमने इसपर सीरियसली सोचा है। अरविन्द बाबू ने जो बात कही ये बात सही है कि इन 7-8 सदस्यों के बारे में, मैं भी आठ-दस ए0जी0एम0 में रहा हूँ, हम जानकर इसको ए0जी0एम0 में रखते हैं क्योंकि वो आठ मेम्बर का दोष नहीं है। ~~तब~~ आपको जैसे आज यहां सरकारी संस्थानों में ई0डी0 और

C.B.I. हो रहा है आपको भी फेस करना होगा। किस सेक्रेट्री ने रजिस्ट्री किया, किस चेयरमेन ने रजिस्ट्री किया, किस बोर्ड ने रजिस्ट्री किया जब आपकी जमीन नहीं थी तो? इसलिए इस बात को हमेशा हमारे सभी माननीय सदस्य ध्यान रखें, कुछ चीजों को परदे में रहने दें। दूसरी बात, आप म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, एक म्यूटेशन जो गलत आदमी द्वारा करा लिया गया था, आपलोग को पहले भी बताया गया कि उस म्यूटेशन को कैंसिल कराया गया, ये कोई नहीं बोलेंगे, अशोक नगर सोसाईटी जहां सब नामी गिरामी लोग हैं और बाहर का दस आदमी गुण्डा आता था और सबको भगा देता था उस म्यूटेशन को कैंसिल करा दिया गया। अब होता है कि उसको WhatsApp पर क्यों नहीं डाला गया। WhatsApp पर हम विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी बात, म्यूटेशन की बात आपने कहा, आपको अवगत करा दें कि म्यूटेशन कितना आसान है झारखण्ड में और राँची में, हमको लगता है यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग जान रहे होंगे। संजय जी एडवोकेट हैं, सब लोग जानते हैं म्यूटेशन कितना आसान है। डिमार्केशन की बात किया है, म्यूटेशन के लिए हमलोगों ने कागज जो चाहिए किसी सदस्य के पास अगर डिटेल्स है इस सोसाईटी के जमीन का तो वो हमको दीजिए। अगर जमीन के कागजात हमको दे दें कि किस खाते में कितना रकबा है, मैं वादा करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, बोर्ड की हैसियत से नहीं कि मैं 06 महीने से लेकर एक साल में करा दूंगा लेकिन कोई कागज नहीं है हमारे पास। अभी हमलोग ने डिस्ट्रीक्ट लैंड एक्विजिशन आफिसर को डी0सी0 से कहलवाया, आप जाईयेगा तो वो फाईल पढ़ ही नहीं पाईयेगा। अपील में गये, अभी हमारे एडवोकेट प्रताप सिंह ने सिविल कोर्ट में समिट पेपर है वो निकाले हैं तो उसमें रकबा नहीं है। हाउसिंग बोर्ड में हर दो दिन पर जाईये वहां बात हुई है कि वो फाईल निकालकर कम से कम हमको एक शिड्यूल तो दीजिए। क्योंकि जो लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन हुआ है उसमें Delivery of पोजीशन ऑफ लैंड का कहीं जिक्र ही नहीं है। 152 एकड़, हमलोगों ने बोर्ड में तय किया था आपको फिर बता दूं कि सभी लोग बैठे थे ऑफ दि रिकार्ड बैठक करके नहीं, हमने ये किया कि अब हम सी0ओ0 को एक पत्र लिखेंगे उसमें दो लाख लगे, तीन लाख लगे, चार लाख लगे, वो दो अमीन को बहाल करें, आठ-दस अमीन हमलोग भी देंगे प्राईवेटली और उनको सपोर्ट करके इसका एक शिड्यूल तैयार कराया जाय। ये चिट्ठी भी बनाये फिर

चिट्ठी बनाने के बात हमको दूसरा थॉट आया कि यदि आज हम यह काम करा दें सोसाईटी अशोक नगर जिसमें बनी है उसमें लैंड का कोई वैल्यू नहीं था। किसी न किसी वजह से उस एक्विजिशन में कोई खाता ऐसा है जो एक्वायर नहीं हुआ है और इसमें गया है। उसके बाद हम बैंकफूट पर आये और पहले सोचे कि ऐसा न हो कि सरकार में हमलोग अपना ही काम करने के लिए फंस जायें क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ हैं जमीन की अगर इस 152 एकड़ में कोई भी खाता ऐसा हो जायेगा जो आपके डिलीवरी ऑफ पोजिशन में नहीं है तो क्या होगा? मान लीजिए व्यक्तिगत लाभ के लिए, न वर्मा साहब को कुछ होगा न हमको कुछ होगा क्योंकि हमलोग भीतर हैं लेकिन जो रोड किनारे हैं अगर गडबड़ा गया तो क्या होगा? तब हमने उसको रोक दिया है और ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन के लिए रुके हुए हैं लोग लेकिन आपको लगता है क्या, हम तो कहते हैं, आज अनुरोध करते हैं कि म्यूटेशन के लिए वर्मा साहब ही अध्यक्षता में एक कमिटी आपलोग 05 आदमी का बनाईये और म्यूटेशन में लगिये हम सारा सपोर्ट करेंगे। ये होना चाहिए, सबका इनभॉल्बमेंट होना चाहिए।

डॉ० माधव, अध्यक्ष : आम सभा द्वारा बजट पारित हो गया है, वो ठीक है। ध्वनिमत से पारित हुआ है। बजट हो गया है। तो ये तीन चीजें जो सोसाईटी के लिए महत्वपूर्ण था, इंडीभ्यूजुअल पानी और बिजली की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि हमलोगों ने, हमारे बोर्ड ने क्रान्ति ला दिया है, जो करना है अपनी संतुष्टी के जॉब से लोग कर रहे हैं जिम्मेवारी मिली है लोग कर रहे हैं। आज से दो साल पहले बरसात में इस रोड में, चार नम्बर रोड में जहाँ तिवारी साहब रहते हैं, दुर्गंध होता था, आज दुर्गंध नहीं हो रहा है, मार्निंग वाक करते होंगे तो आपलोग भी देखते होंगे, हम उसपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इन दो महत्वपूर्ण चीजों पर कि क्या ये सोसाईटी चार लाख, पाँच लाख, छः लाख रूपया रेंट प्राप्त करेगा और छः लाख रूपया होल्डिंग देगा शॉपिंग से इसके लिए आपलोग एक कमिटी बनायें रेवेन्यू कहाँ से आयेगा, इनकम कहाँ से आयेगा और प्रदीप जी ने कहा कि आई०ए० फाईल करने का जो अनुपालन वो किया गया है। गत बैठक के बाद आई०ए० फाईल किया मैंने फाईल पर आर्डर किया है डायरेक्टर को कि वो

जाकर आई0 ए0 फाईल करें कि हमारी बात से भी माननीय न्यायालय अवगत हो तब तो आज क्लब है, कल पार्क होगा, कल पार्क डी0 होगा, ये नहीं होगा, ये सोसाईटी का है इसलिए हमने कहा कि सोसाईटी की भी बात को हमलोग रखेंगे, आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप बताईये, आपसे तो हमने मांगा था क्योंकि हमारे फाईल में उपलब्ध नहीं था कि आपको जो सोसाईटी ने, आपको बोर्ड ने, वो ए0जी0एम0 से पारित नहीं है, किसी ए0जी0एम0 में हमने नहीं देखा, आप हमको दीजिए कि कैसे आपको दे दिया गया है। या तो फिर आप देना नहीं चाहते हैं तो क्या सोसाईटी की चीज को, कल क्लब के बगल में जो थाना तोड़ा कोई आकर कब्जा कर ले उसको छोड़ दें? आपलोग बोलिये, हमको क्या है हम क्या कोई लेने जा रहे हैं। इसपर भी विचार कीजिए आपलोग। निगम को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तीन लाख पेनाल्टी हुआ है फिर पेनाल्टी होगा तो फिर पेनाल्टी लगेगा, विषय ये है, इसको भी सोचना होगा आपको कि क्या उन चीजों को जो आपके सोसाईटी की चीज है उसकी आईडेंटिटी दूसरे की हो जाय। हम तो ये नहीं कहा कि क्लब हमको दे दो, हमने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा कि अगर क्लब का पांच आदमी या जो सोसाईटी है वो कहेगा कि क्लब की सम्पति मेरी है तो यह संभव नहीं है। न ही लीज है न एग्रीमेंट है। आपलोग तय कर लीजिए। हमने इसीलिए आई0ए0 फाईल किया कि कोई एडमर्स आदेश नही हो। सोसाईटी की वो चीज है सोसाईटी ने यदि आपको दे दिया है किसी बोर्ड ने, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि गलत किया, सही किया है, कोई लीज है, कोई एग्रीमेंट है, ए0जी0 के रिपोर्ट में आता है कि आपने रेंट क्यों नहीं लिया है, हम पर ये चार्ज हो रहा है। कल अगर उसी पूरे कागज को जो केस भी चल रहा है, आज रजिस्ट्रार के यहाँ चला जाय तो हमारे बोर्ड पर भी वो चार्ज करेगा क्योंकि अगर कोई पुराना ड्यूज है तो हमारी भी जिम्मेदारी है। शॉपिंग कम्पलेक्स के रेंट के संबंध में जिसका भी है हमको किसी से पूर्वाग्रह नहीं है। अब आप बतायें कि तीन-चार रूपया प्रति वर्गफीट सोसाईटी को हमको रेंट आता है और हमको उसके मेंटनेंस, स्टॉफ, हॉल्लिडिंग में आठ लाख, नौ लाख रूपया खर्च होगा तो आपलोग निर्णय ले लीजिए, कमिटी बना दीजिए, आप तय करें कि कितना रेंट होना चाहिए। एक और बात आपको बता दूं कि हमारे डायरेक्टर लोगों ने रिसर्च किया है इस पर। अभी जैसे

72 या 74 जो भी शॉप हैं एग्रीमेंट जिनका फेल कर गया है तो ट्रेड लाईसेंस उनको कैसे मिलेगा? दुकान तिवारी साहब के नाम से एलॉट है, तिवारी साहब ने बेड़ो के किसी आदमी को दे दिया तो क्या यह अधिकार है आपके एग्रीमेंट में? क्या आपका घर कोई किरायेदार लिया है तो वो किसी दूसरे को किराया लगा देगा? विचारणीय है, कि दुकान का किराया 200 रुपये देते हैं और 15000 रूपया में बिना सोसाईटी की अनुमति के किराया लगा दिया। हम उसका हॉल्लिडिंग पाँच गुणा देते हैं इसलिए आपको तय करना होगा। हम कह रहे हैं कि इसको तय करना चाहिए कि क्या वो दुकान आपको दूसरे किरायेदार को लगाने का अधिकार है? किस कानून में है? वर्मा साहब बताईये, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमने अपनी बात रख दिया आपके पास। प्रदीप जी बतावें, अजय जी बतावें, संजय जी बतावें, सारे लोग बतावें कि किरायादार किसी दूसरे को किराया लगा सकता है। यदि ऐसा हुआ है तो मूल आवंटी का एग्रीमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा। बस इतना ही कहना है और ये हम इसीलिए कहे क्योंकि आपका

अनुभव है, आपने बहुत सारे माईक्रोस्कोपिक विश्लेषण गत बैठक में प्रस्तुत किए गए विवरणी पर किया है। उसमें हमने सुधार भी किया लेकिन सोसाईटी का कंसेप्ट अलग होता है, गवर्नमेंट फंक्सनिंग अलग होती है। पुराने बोर्ड ने भी काम किया, कोशिश किया, सरकार में काम कराना बहुत आसान नहीं है। हम भी सरकारी आदमी रहे हैं जानते हैं कि आसान नहीं है लेकिन लोग लगे हुए हैं। कभी शंकर जी एम0एल0ए0 के यहाँ जाते हैं कि एक गाड़ी हमको दे दीजिए। कभी प्रताप जी जाते हैं, कोशिश करता है आदमी लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि कोशिश कर रहे हैं तो हो ही जाय। फिर भी हमलोगों ने बहुत कोशिश किया है जो आज तक नहीं हुआ था वो हुआ है। हमको प्रशंसा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हमारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है, गाली हमको दें हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि कुछ टेक्निकलिटीज हो सकती है उसमें कमियां हों इसको इस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। सोसाईटी के हित के तीन मुद्दों की चर्चा हमने कर दिया। म्यूटेशन के लिए एक कमिटी, रेंट के लिए एक कमिटी, बनाया जायेगा और 7 प्लॉट के बारे में वकीलों की एक कमिटी बना

W

M

कर आगे की कार्रवाई की जाएगी । हमको बोलिये, हमलोग बैल की तरह, पायलट की तरह आगे जहाज को चला देंगे । आज की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत बजट का घटनोत्तर अनुमोदन, प्रस्तावित बजट(2023-24 एवं 2024-25(चार माह) का ध्वनिमत से पारित किया गया है । श्री वर्मा साहब ने गत बैठक की कार्यवाही की औपचारिक सम्पुष्टि का प्रस्ताव नहीं है, जो सच से परे है । कार्यावली की विषय सूची क्रमांक (3) में सम्पुष्टि का स्पष्ट उल्लेख है ।

(1) नये आगंतुक सदस्यों का स्वागत किया गया ।

(2) दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गयी ।

श्रीमती शोभा कुमारी: माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय एवं निदेशक मण्डल के सदस्यगण, आप सबों की ओर से मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मिला इसके लिए मैं आभारी हूँ ।

सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी ।

आज दिनांक-10 सितम्बर 2023 के साधारण आम सभा की बैठक में आपने बहुमूल्य विचार रखे, बजट में व्यय हेतु स्वीकृति दी है और भी बहुत सारे हमारे प्रगतिशील कार्यों का आपने समर्थन किया है ।


यह सब आनेवाले समय में हमें कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाने में काफी मदद मिलेगी । इस सभा को सुचारु रूप से संपन्न करने में हमारे कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने जो सहयोग दिया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी । एक बात पुनः आप सबों को सभा में सम्मिलित होने के लिए धन्यवाद । नमस्कार ।


अध्यक्ष



ज्ञापांक :- 398 दिनांक :- 8/10/23

प्रतिलिपि - निदेशक मण्डल के सभी सदस्यों / सभी माननीय सदस्यों को
सूचनार्थ सादर समर्पित ।


अवैतनिक सचिव ।
8-10-23